



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-13062020-219926  
CG-DL-E-13062020-219926

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1  
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 145]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 12, 2020/ज्येष्ठ 22, 1942

No. 145]

NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 12, 2020/JYAISTHA 22, 1942

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 जून, 2020

मामला सं. एडीडी(ओआई) 33/2019

प्राथमिक जांच परिणाम

**विषय:** चीन जन. गण. से "एनिलिन" के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच।

**फा. सं. 6/42/2019-डीजीटीआर.—क. मामले की पृष्ठभूमि**

1. मैसर्स गुजरात नर्मदा वैली फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड (जिसे यहां आगे "आवेदक" भी कहा गया है) ने चीन जनवादी गणराज्य (जिसे यहां आगे "संबद्ध देश" भी कहा गया है) से "एनिलिन" (जिसे यहां आगे "विचाराधीन उत्पाद" अथवा "पीयूसी" अथवा "संबद्ध सामान" भी कहा गया है) के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच शुरू करने के लिए समय-समय पर यथा संशोधित सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 (जिसे बाद में अधिनियम कहा गया है) और समय-समय पर यथा संशोधित सीमा प्रशुल्क (पाटित आयातों पर पाटनरोधी शुल्क की जांच, मूल्यांकन एवं संग्रहण तथा क्षति के निर्धारण के लिए) नियमावली, 1995 (जिसे आगे यहां "नियमावली" भी कहा गया है) के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी के समक्ष एक आवेदन पत्र दायर किया।
2. प्राधिकारी ने आवेदक द्वारा प्रस्तुत पर्याप्त प्रथम दृष्टया साक्ष्य के आधार पर संबद्ध देश के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध सामानों के तथाकथित पाटन की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव निर्धारित करने के लिए

और पाटनरोधी शुल्क की राशि, जो यदि लगाई जाए और घरेलू उद्योग को तथाकथित क्षति समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगी, की सिफारिश करने के लिए नियमावली के नियम 5 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9क के अनुसार संबद्ध जांच शुरू करते हुए भारत के राजपत्र में प्रकाशित दिनांक 24 जनवरी, 2020 की अधिसूचना संख्या 33/2019-डीजीटीआर द्वारा एक सार्वजनिक सूचना जारी की।

**ख. प्रक्रिया**

3. संबद्ध जांच के संबंध में नीचे वर्णित प्रक्रिया अपनाई गई है:

- क. प्राधिकारी ने उपर्युक्त नियमावली 5 के उप नियम (5) के अनुसार जांच की शुरुआत करने से पूर्व वर्तमान पाटनरोधी जांच संबंधी आवेदन पत्र प्राप्त होने के संबंध में भारत में संबद्ध देश के दूतावास को अधिसूचित किया।
- ख. प्राधिकारी ने संबद्ध देश से संबद्ध सामानों के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच शुरू करते हुए भारत के राजपत्र असाधारण में प्रकाशित दिनांक 24 जनवरी, 2020 की सार्वजनिक सूचना जारी की।
- ग. भारत में संबद्ध देश के दूतावास को नियमावली के नियम 6(2) के अनुसार, जांचों की शुरुआत करने के संबंध में सूचित किया गया था। प्राधिकारी ने संबद्ध देश की सरकार को भारत में उसके दूतावास के माध्यम से, संबद्ध देश के ज्ञात उत्पादकों/ निर्यातकों, ज्ञात आयातकों तथा घरेलू उद्योग और आवेदक द्वारा उपलब्ध कराए गए पतों के अनुसार अन्य घरेलू उत्पादकों को जांच की शुरुआत की अधिसूचना की प्रति भेजी और उनसे अनुरोध किया कि वे निर्धारित समय-सीमा के भीतर लिखित में अपने ज्ञात विचार दें।
- घ. प्राधिकारी ने उपर्युक्त नियमावली के नियम 6(3) के अनुसार, ज्ञात उत्पादकों/ निर्यातकों तथा संबद्ध देश की सरकार को भारत में उनके दूतावास के माध्यम से आवेदन पत्र के अगोपनीय रूपांतर की प्रति उपलब्ध कराई। आवेदन पत्र के अगोपनीय रूपांतर की एक प्रति सार्वजनिक फाइल में भी उपलब्ध कराई गई थी और जहां अनुरोध किया गया था, वहां अन्य हितबद्ध पक्षकारों को भी उपलब्ध कराई गई थी।
- ङ. प्राधिकारी ने संबद्ध देश के ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों, भारत में ज्ञात आयातकों/ प्रयोक्ताओं, आवेदक द्वारा उपलब्ध कराए गए पतों के अनुसार अन्य भारतीय उत्पादकों तथा घरेलू उद्योग को भी सूचना की प्रति भेजी और उनसे अनुरोध किया कि वे जांच की शुरुआत में दी गई समय सीमा के भीतर लिखित में अपने ज्ञात विचार दें।
- च. भारत में संबद्ध देश के दूतावास से यह भी अनुरोध किया गया था कि वे अपने देश के निर्यातकों/उत्पादकों को निर्धारित समय-सीमा के भीतर प्रश्नावली का उत्तर देने की सलाह दें। उत्पादकों/निर्यातकों को भेजे गए पत्र और प्रश्नावली की प्रति संबद्ध देश के ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों के नामों और पतों के साथ उन्हें भेजी गई थी।
- छ. प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार संबद्ध देश में ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों को निर्यातक प्रश्नावली भेजी:
  - i. मैसर्स सिनोपेक नानजिंग केमिकल इंडस्ट्रीज कं. लिमिटेड
  - ii. मैसर्स बेयर मैटेरियल साइंस (शंघाई) कं. लिमिटेड
  - iii. मैसर्स जिलिन कॉनेल केमिकल इंडस्ट्री कं. लिमिटेड
  - iv. मैसर्स शांक्सी तियांजी कोल केमिकल ग्रुप कं. लिमिटेड
  - v. मैसर्स शानडोंग जिनलिंग केमिकल कं. लिमिटेड
  - vi. मैसर्स जियांग्सु रुक्सियांग केमिकल कं. लिमिटेड
  - vii. मैसर्स हेनन कैपू केमिकल कं. लिमिटेड
  - viii. मैसर्स बीएएसएफ (चीन) कं. लिमिटेड
  - ix. मैसर्स यंताई वनहुआ पॉलीथेन कं. लिमिटेड

- x. मैसर्स हेबेई जिहेंग केमिकल ग्रुप कं. लिमिटेड
  - xi. मैसर्स शानडोंग हैहुआ कं. लिमिटेड
- ज. उपर्युक्त अधिसूचना के उत्तर में, निम्नलिखित उत्पादकों, उनके संबद्ध निर्यातकों/ व्यापारियों ने निर्यातक प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत किया है:
- i. मैसर्स वनहुआ केमिकल ग्रुप कं. लिमिटेड
  - ii. मैसर्स वनहुआ केमिकल (हांगकांग) कं. लिमिटेड
  - iii. मैसर्स केम्पर एनर्जी पीटीई. लिमिटेड
  - iv. मैसर्स वनहुआ केमिकल (यंताई) ट्रेडिंग कं. लिमिटेड
  - v. मैसर्स वनहुआ केमिकल (निंगबो) कं. लिमिटेड
  - vi. मैसर्स वनहुआ केमिकल (निंगबो) ट्रेडिंग कं. लिमिटेड
- झ. प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार, आवश्यक सूचना मंगाने हुए भारत में संबद्ध सामानों के निम्नलिखित ज्ञात आयातकों/प्रयोक्ताओं को प्रश्नावलियां भेजीं:
- i. मैसर्स एनओसीआईएल लिमिटेड
  - ii. मैसर्स आरती इंडस्ट्रीज लिमिटेड
  - iii. मैसर्स बोडल केमिकल्स लिमिटेड
  - iv. मैसर्स भगेरिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड
  - v. मैसर्स कच्छ केमिकल्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड
  - vi. मैसर्स मयूर डाइकेम इंटरमीडिएट एलएलपी
  - vii. मैसर्स इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट्स एंड केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
- ञ. उपर्युक्त अधिसूचना के उत्तर में, निम्नलिखित आयातकों/प्रयोक्ताओं ने आयातक प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत किया है:
- i. मैसर्स भगेरिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड
  - ii. मैसर्स बोडल केमिकल्स लिमिटेड
  - iii. मैसर्स कच्छ केमिकल्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड
  - iv. मैसर्स कलरटेक्स इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड
  - v. मैसर्स मयूर डाई केम इंटरमीडिएट्स एलएलपी
- ट. इसके अतिरिक्त, निम्नलिखित हितबद्ध पक्षकारों ने जांच पर कानूनी अनुरोध दायर किए हैं:
- i. मैसर्स जेम्बी केम लिमिटेड
  - ii. मैसर्स भारत ऑर्गेनिक्स लिमिटेड
  - iii. मैसर्स नूतन डाई केम प्राइवेट लिमिटेड
  - iv. मैसर्स रेमिक केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
  - v. मैसर्स लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज लिमिटेड
  - vi. द डाईस्टफ्स मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (डीएमएआई)

- vii. मैसर्स वनहुआ केमिकल ग्रुप कं. लिमिटेड, मैसर्स वनहुआ केमिकल (हांगकांग कं. लिमिटेड, मैसर्स वनहुआ केमिकल (यंताई) ट्रेडिंग कं. लिमिटेड, मैसर्स वनहुआ केमिकल (निंगबो) कं. लिमिटेड, और मैसर्स वनहुआ केमिकल (निंगबो) ट्रेडिंग कं. लिमिटेड सामूहिक रूप से।
- ठ. प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों के लिए ई-मेल के माध्यम से ई-फाइल के रूप में विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों प्रस्तुत साक्ष्य का अगोपनीय रूपांतर उपलब्ध कराया।
- ड. वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय (डीजीसीआईएंडएस) से अनुरोध किया गया था कि वे पिछले तीन वर्षों तथा जांच की अवधि के लिए संबद्ध सामानों के आयातों के लेन-देन वार ब्यौरे उपलब्ध कराएं जो प्राधिकारी को प्राप्त हो गए थे। प्राधिकारी ने आयातों की मात्रा और मूल्य का परिकलन करने और लेन-देनों की उचित जांच करने के बाद अपने विश्लेषण के लिए डीजीसीआईएंडएस के आंकड़ों पर विश्वास किया है।
- ढ. सामान्यतया स्वीकृत लेखाकरण सिद्धांतों (जीएएपी) और नियमावली के अनुबंध-III के आधार पर घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना के आधार पर भारत में संबद्ध सामानों की इष्टतम उत्पादन लागत और निर्माण एवं बिक्री लागत के आधार पर क्षति रहित कीमत (एनआईपी) निकाली गई है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि क्या पाटन मार्जिन से कम पाटनरोधी शुल्क घरेलू उद्योग को क्षति समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगा।
- ण. आवेदक द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों/आंकड़ों को आवश्यक समझी गई सीमा तक सत्यापित किया गया है और प्राथमिक जांच परिणाम के प्रयोजन के लिए उस पर विश्वास किया गया है।
- त. वर्तमान जांच के प्रयोजन के लिए जांच की अवधि 1 अप्रैल, 2019 से 30 सितंबर, 2019 (6 माह) है। तथापि, क्षति जांच अवधि 2016-17, 2017-18, 2018-19 और जांच की अवधि मानी गई है।
- थ. गोपनीय आधार पर हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दी गई सूचना की जांच गोपनीयता के दावे की पर्याप्तता के संबंध में की गई थी। संतुष्ट होने पर प्राधिकारी ने जहां भी आवश्यक था, गोपनीयता के दावों को स्वीकार किया है और उस सूचना को गोपनीय माना गया है तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों को प्रकट नहीं की गई है। जहां भी संभव हुआ, गोपनीय आधार पर सूचना देने वाले पक्षकारों को निर्देश दिया गया था कि वे गोपनीय आधार पर दायर सूचना का पर्याप्त अगोपनीय रूपांतर उपलब्ध कराएं।
- द. जहां कहीं किसी हितबद्ध पक्षकार ने सूचना देने से इंकार किया है अथवा वर्तमान वर्तमान जांच प्रक्रिया के दौरान अन्यथा आवश्यक सूचना नहीं दी है अथवा जांच में काफी बाधा डाली है, वहां प्राधिकारी ने उन पक्षकारों को असहयोगी माना है तथा उपलब्ध तथ्यों के आधार पर प्राथमिक जांच परिणाम रिकार्ड किए हैं।
- ध. प्राधिकारी ने वर्तमान जांच में साक्ष्यों के समर्थित तथा संगत मानी गई सीमा तक इस स्तर पर सभी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उठाए गए सभी तर्कों और दी गई सूचना पर विचार किया है। प्राधिकारी आगे प्राथमिक जांच परिणाम के बाद हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यपरक दस्तावेजों की जांच करेंगे जो अंतिम जांच परिणाम के समय निष्कर्षों के लिए आधार बनेंगे।
- न. इस अधिसूचना में \*\*\*\* किसी हितबद्ध पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना तथा प्राधिकारी द्वारा नियमावली के तहत मानी गई सूचना दर्शाते हैं।
- प. संबद्ध जांच के लिए प्राधिकारी द्वारा अपनाई गई विनिमय दर 1 अमेरिकी डॉलर = 70.73 रुपए है।

#### ग. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु

4. जांच की शुरुआत के स्तर पर, विचाराधीन उत्पाद निम्नलिखित रूप में परिभाषित किया गया था:

"वर्तमान जांच के प्रयोजन के लिए विचाराधीन उत्पाद "एनिलिन" है जिसे "एनिलिन तेल" के रूप में भी जाना जाता है। एनिलिन एक पारदर्शी, तैलीय द्रव है और एक प्राथमिक अमीन सम्मिश्रण है। इसका रंग ताजा-ताजा डिस्टिल्ड किए जाने पर हल्का पीला-पीला द्रव में बदल जाता है। रोशनी अथवा हवा में रखने पर इसका रंग गहरा हो जाता है। एनिलिन औषधियों, फार्मास्युटिकल, डाई तथा डाई मध्यवर्तियों जैसे महत्वपूर्ण उद्योगों के लिए अनिवार्य आधारभूत ऑर्गेनिक रसायन है।

संबद्ध उत्पाद कोड 29214110 के अंतर्गत अध्याय 29 के तहत वर्गीकृत है। सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल संकेतात्मक है और किसी भी तरह उत्पाद क्षेत्र पर बाध्यकारी नहीं है।"

### ग.1 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

5. विचाराधीन उत्पाद के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

क) विचाराधीन उत्पाद एनिलिन है जिसे एनिलिन तेल के रूप में भी जाना जाता है जो कि एक पारदर्शी तैलीय द्रव है और औषधियों, फार्मास्युटिकल, डाई तथा डाई मध्यवर्तियों में प्रयुक्त किया जाता है।

ख) यह उत्पाद सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 के सीमा शुल्क शीर्ष 29214110 के तहत वर्गीकृत है।

ग) आवेदक द्वारा उत्पादित सामान आयातित सामानों की समान वस्तु हैं क्योंकि वे भौतिक एवं रासायनिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया एवं प्रौद्योगिकी, प्रकार्य एवं प्रयोग, उत्पाद विशिष्टियों, कीमत, वितरण एवं विपणन तथा सामानों के प्रशुल्क वर्गीकरण के संदर्भ में तुलनीय हैं और तकनीकी तथा वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय है। घरेलू उद्योग तथा संबद्ध देश के उत्पादकों द्वारा लगाई गई प्रौद्योगिकी में कोई ज्ञात महत्वपूर्ण अंतर नहीं है।

### ग.2 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

6. विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र के संबंध में किसी अन्य हितबद्ध पक्षकार द्वारा कोई अनुरोध नहीं किये गए हैं।

### ग.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

7. विचाराधीन उत्पाद से संबंधित मुद्दों के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोधों की निम्नलिखित रूप में जांच की गई है और उन्हें हल किया गया है।

8. वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद एनिलिन है जो औषधियों, फार्मास्युटिकल, डाई और डाई मध्यवर्तियों के लिए एक आधारभूत ऑर्गेनिक रसायन है। इस उत्पाद को एनिलिन तेल भी कहा जाता है।

9. प्राधिकारी ने विचाराधीन उत्पाद को निम्नलिखित रूप में माना है:

"वर्तमान जांच के प्रयोजन के लिए विचाराधीन उत्पाद "एनिलिन" है जिसे "एनिलिन तेल" के रूप में भी जाना जाता है। एनिलिन एक पारदर्शी, तैलीय द्रव है और एक प्राथमिक अमीन सम्मिश्रण है। इसका रंग ताजा-ताजा डिस्टिल्ड किए जाने पर हल्का पीला-पीला द्रव में बदल जाता है। रोशनी अथवा हवा में रखने पर इसका रंग गहरा हो जाता है। एनिलिन औषधियों, फार्मास्युटिकल, डाई तथा डाई मध्यवर्तियों जैसे महत्वपूर्ण उद्योगों के लिए अनिवार्य आधारभूत ऑर्गेनिक रसायन है।

संबद्ध उत्पाद कोड 29214110 के अंतर्गत अध्याय 29 के तहत वर्गीकृत है। सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल संकेतात्मक है और किसी भी तरह उत्पाद क्षेत्र पर बाध्यकारी नहीं है।"

10. रिकार्ड में उपलब्ध सूचना से यह नोट किया गया है कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित उत्पाद संबद्ध देशों से आयातित विचाराधीन उत्पाद की समान वस्तु है। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित उत्पाद और संबद्ध देशों से आयातित संबद्ध सामान भौतिक एवं रासायनिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया एवं प्रौद्योगिकी, प्रकार्य एवं प्रयोग, उत्पाद विशिष्टियों, कीमत, वितरण एवं विपणन तथा सामानों के प्रशुल्क वर्गीकरण के संदर्भ में तुलनीय है। ये दोनों तकनीकी एवं वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं। उपभोक्ताओं ने इन दोनों का प्रयोग परस्पर परिवर्तनीय रूप से किया है और कर रहे हैं। आवेदक के तर्क पर अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा विवाद नहीं किया गया है। प्राधिकारी अनंतिम रूप से मानते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध सामान पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(घ) के अनुसार संबद्ध देशों से आयातित उत्पाद की समान वस्तु हैं।

11. विचाराधीन उत्पाद प्रशुल्क कोड 29214110 के तहत अध्याय शीर्ष 29 के अंतर्गत वर्गीकृत है। सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल संकेतात्मक है और विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र पर बाध्यकारी नहीं है।

**घ. घरेलू उद्योग का क्षेत्र एवं आधार****घ.1 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध**

12. घरेलू उद्योग के क्षेत्र एवं आधार के संबंध में घरेलू उद्योग ने निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

- क. आवेदक भारत में संबद्ध सामानों का एक मात्र उत्पादक है।
- ख. आवेदक ने संबद्ध देश से संबद्ध सामानों का आयात नहीं किया है और संबद्ध देश में किसी निर्यातक अथवा भारत में संबद्ध सामानों के आयातक से संबद्ध नहीं है।
- ग. आवेदक नियमावली के नियम 2(ख) और नियम 5(3) की अपेक्षाएं पूरी करता है।

**घ.2 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध**

13. घरेलू उद्योग के क्षेत्र और आधार के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा कोई अनुरोध नहीं किए गए हैं।

**घ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच**

14. पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) में घरेलू उद्योग निम्नलिखित रूप में परिभाषित है:

“घरेलू उद्योग” का तात्पर्य ऐसे समग्र घरेलू उत्पादकों से है जो समान वस्तु के विनिर्माण और उससे जुड़े किसी कार्यकलाप में संलग्न हैं अथवा ऐसे उत्पादकों से है जिनका उक्त वस्तु का सामूहिक उत्पादन उक्त वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा भाग बनता है सिवाए उस स्थिति के जब ऐसे उत्पादक आरोपित पाटित वस्तु के निर्यातकों या आयातकों से संबंधित होते हैं अथवा वे स्वयं उसके आयातक होते हैं, तो ऐसे मामले में “घरेलू उद्योग” पद का अर्थ शेष उत्पादकों के संदर्भ में लगाया जा सकता है।”

15. यह आवेदन पत्र मैसर्स गुजरात नर्मदा वैली फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है। भारत में संबद्ध सामानों का कोई अन्य उत्पादक नहीं है। आवेदक ने संबद्ध देश से संबद्ध सामानों का आयात नहीं किया है और संबद्ध देश में किसी निर्यातक अथवा भारत में किसी आयातक से संबद्ध नहीं है।

16. तदनुसार, प्राधिकारी मानते हैं कि आवेदक नियमावली के नियम 2(ख) के अभिप्राय से घरेलू उद्योग है और मानते हैं कि आवेदन पत्र नियमावली के नियम 5(3) के अनुसार आधार के मानदंडों को पूरा करता है।

**गोपनीयता****घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध**

17. गोपनीयता के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा कोई अनुरोध नहीं किये गये हैं।

**अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध**

18. याचिकाकर्ता द्वारा अत्यधिक गोपनीयता का दावा किया गया है क्योंकि इसने याचिका के खंड VI में कोई सूचना प्रदान नहीं की है क्योंकि यह एक बहु उत्पाद कंपनी है। अतः वार्षिक रिपोर्ट में विचाराधीन उत्पाद के संबंध में सूचना प्रदान नहीं करती। यद्यपि संबद्ध सामानों की क्षमता और क्षमता उपयोग वार्षिक रिपोर्ट में प्रकट किए गए हैं। तथापि, इसे गोपनीय होने का भी दावा किया गया है।

**प्राधिकारी द्वारा जांच**

19. गोपनीयता के संबंध में जांच प्रक्रिया के दौरान आवेदक तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए विभिन्न अनुरोधों की प्राधिकारी द्वारा संगत समझी गई सीमा तक जांच की गई है और निम्नलिखित रूप में उन्हें हल किया गया है।

20. प्राधिकारी ने नियम 6(7) के अनुसार, निरीक्षण के लिए विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों के अगोपनीय रूपांतर से युक्त सार्वजनिक फाइल के माध्यम से सभी हितबद्ध पक्षकारों को विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दी गयी सूचना का अगोपनीय रूपांतर उपलब्ध कराया।

(i) सूचना की गोपनीयता के संबंध में, पाटनरोधी नियमावली के नियम 7 में निम्नलिखित प्रावधान है:

“गोपनीय सूचना: (1) नियम 6 के उपनियमों (2), (3) और (7), नियम 12 के उपनियम (2), नियम 15 के उपनियम (4) और नियम 17 के उपनियम (4) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी जांच की



प्रक्रिया में नियम 5 के उपनियम (1) के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों के प्रतियां या किसी पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर निर्दिष्ट प्राधिकारी को प्रस्तुत किसी अन्य सूचना के संबंध में निर्दिष्ट प्राधिकारी उसकी गोपनीयता से संतुष्ट होने पर उस सूचना को गोपनीय मानेंगे और ऐसी सूचना देने वाले पक्षकार से स्पष्ट प्राधिकार के बिना किसी अन्य पक्षकार को ऐसी किसी सूचना का प्रकटन नहीं करेंगे।

(2) निर्दिष्ट प्राधिकारी गोपनीय अधिकारी पर सूचना प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों से उसका अगोपनीय सारांश प्रस्तुत करने के लिए कह सकते हैं और यदि ऐसी सूचना प्रस्तुत करने वाले किसी पक्षकार की राय में उस सूचना का सारांश नहीं हो सकता है तो वह पक्षकार निर्दिष्ट प्राधिकारी को इस बात के कारण संबंधी विवरण प्रस्तुत करेगा कि सारांश करना संभव क्यों नहीं है।

(3) उप नियम (2) में निहित किसी बात को होते हुए भी यदि निर्दिष्ट प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हो कि गोपनीयता के लिए अनुरोध न्यायसंगत नहीं अथवा सूचना प्रदाता सूचना को सार्वजनिक करने अथवा इसको सामान्य तौर पर अथवा संक्षिप्त रूप में उसे प्रकट करने के लिए अनिच्छुक हो, तो ऐसी सूचना की उपेक्षा की जा सकती है।

(ii) जहां तक सूचना की गोपनीयता के संबंध में शर्तों का संबंध है, यह नोट किया जाता है कि हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर दी गई सूचना की जांच गोपनीयता के दावे की पर्याप्तता के संबंध में की गई थी। संतुष्ट होने पर प्राधिकारी ने जहां भी आवश्यक था, गोपनीयता के दावों को स्वीकार किया है और उस सूचना को गोपनीय माना गया है तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों को प्रकट नहीं की गई है। जहां भी संभव हुआ, गोपनीय आधार पर सूचना देने वाले पक्षकारों को निर्देश दिया गया था कि वे गोपनीय आधार पर दायर सूचना का पर्याप्त अगोपनीय रूपांतर उपलब्ध कराएं। प्राधिकारी ने सार्वजनिक फाइल के रूप में विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों का अगोपनीय रूपांतर उपलब्ध कराया। घरेलू उद्योग के आयातों, निष्पादन मानदंडों और क्षति मानदंडों से संबंधित सूचना सार्वजनिक फाइल में उपलब्ध कराई गई है। व्यापार संवेदी सूचना को परिपाटी के अनुसार गोपनीय रखा गया है।

## ड. विविध अनुरोध

### ड.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध

21. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने विविध मुद्दों के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

- क. आवेदक ने जांच की शुरुआत के लिए शर्त साबित करने के लिए कोई महत्वपूर्ण साक्ष्य नहीं दिया है और इसके बजाए आयात बढ़ा चढ़ाकर दिए हैं तथा क्षति बनाई है। गलत और अपर्याप्त आंकड़ों के साथ केवल अवधारणाएं और झूठा विवरण है।
- ख. एनिलिन के प्रयोक्ता कीमत संवेदी और प्रतिस्पर्धी बाजार में कार्य कर रही प्राथमिक रूप से लघु एवं मध्य पैमाने की यूनिटें हैं। पाटनरोधी शुल्क लगाने से उस पर प्रभाव पड़ेगा जो कि पहले ही मंदी तथा इनपुट रसायनों की बढ़ी हुई लागत झेल रही है।
- ग. जांच की अवधि प्राधिकारी की विगत परिपाटी का विचलन है। यहां तक कि न्यूजप्रिंट की हाल ही में शुरू की गई जांच में प्राधिकारी ने जांच की अवधि नौ माह अपनाई, जब याचिकाकर्ता ने जांच की छः माह की अवधि का अनुरोध किया था। वह भी अन्य सदस्यों द्वारा अपनाई गई परिपाटी से विचलन है।
- घ. मानक प्रचालन प्रक्रिया (एसओपी) के पैरा 5.10 के अनुसार, जांच की अवधि 12 माह होनी चाहिए। प्राधिकारी द्वारा कोई औचित्य नहीं दिया गया है।
- ङ. जांच की 6 माह की अवधि वर्ष 2018-19 में घरेलू उद्योग द्वारा 27 दिन के रख-रखाव के कारण मंदी के प्रभाव को छिपाने के लिए चुनी गई है। परिणामस्वरूप, जांच की अवधि केवल 5 माह के लिए रख दी गई है।
- च. वर्तमान मामले में जांच की 6 माह की अवधि मानने के लिए औचित्य नहीं दर्शाया गया है। क्षति की जांच करने के लिए व्यापार से जुड़े सभी चक्रीय प्रभावों पर विचार करने के लिए कम से कम एक वर्ष की अवधि ली जानी चाहिए।

- छ. जांच की अवधि की अनुपयुक्तता भी उतार-चढ़ाव वाली मासिक आयात कीमतों से देखी जा सकती है। याचिकाकर्ता ने जांच की अवधि में आयात कीमत में गिरावट का दावा किया है। तथापि, जांच की अवधि में कीमत 6 प्रतिशत तक बढ़ी है जो क्षति विश्लेषण के लिए कम अवधि की अनुपयुक्तता दर्शाती है।
- ज. कच्ची सामग्री की कमी से निचले स्तर के उत्पादों के उत्पादन में व्यवधान होगा। शुल्क की सिफारिश केवल तभी की जाए, यदि स्थानीय उत्पादकों की क्षमताएं मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त हों।
- झ. चीन में निचले स्तर के उत्पाद भी विनिर्मित किए जाते हैं जो भारत को तथा यूरोपीय संघ और एशिया में भारतीय उत्पादकों के अन्य ग्राहकों को भेजे जा रहे हैं।
- ञ. कोविड-19 महामारी के प्रभाव एसएमई/एमएसएमई में डाईस्टफ उत्पादकों पर दिखाई देते हैं और इनपुट पर किसी अतिरिक्त शुल्क से कई यूनितें स्थायी रूप से बंद हो जाएंगी।
- ट. आवेदक मांग को पूरा नहीं कर सकता और इसीलिए आयात होने जारी रहेंगे। शुल्क से आवेदक कीमत में फेरबदल कर पाएगा और अपना लाभ बढ़ा पाएगा।

## इ.2 प्राधिकारी द्वारा जांच

22. प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों के विचारों पर निम्नलिखित रूप में विचार किया है:

- क. 6 माह की जांच की अवधि के चयन के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध के संबंध में प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच की अवधि के रूप में 6 माह की अवधि अपनाना नियमावली के विपरीत नहीं है। घरेलू उद्योग ने जांच की अवधि (पीओआई) के रूप में अप्रैल, 2019 से सितंबर, 2019 (6 माह) मानने की आवश्यकता सिद्ध की। प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग द्वारा दिए गए कारणों से संतुष्ट होने पर उसे स्वीकार किया। प्राधिकारी मानते हैं कि वर्तमान मामले में 6 माह की जांच की अवधि उपयुक्त है क्योंकि संबद्ध देश से आयात कीमतों में गिरावट अप्रैल-सितंबर, 2019 में बहुत अधिक है। वर्तमान मामले में याचिका 27 दिसंबर, 2019 को दायर की गई थी और इसीलिए सितंबर, 2019 के बाद की अवधि के लिए आंकड़े जांच की शुरुआत के स्तर पर उपलब्ध नहीं थे। पाटनरोधी जांच का प्रयोजन यह जांच करना है कि क्या उत्पाद का पाटन किया गया है और क्या इस पाटन से घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है। इस प्रकार, प्राधिकारी नोट करते हैं कि इस मामले के लिए चुनी गई जांच की अवधि जांच की शुरुआत के समय कानूनी स्थिति तथा प्राधिकारी द्वारा अपनाई जा रही परिपाटी के अनुरूप है। यह भी नोट किया जाता है कि नियमावली में दिनांक 2 फरवरी, 2020 की सीमा शुल्क अधिसूचना संख्या 9/2020-सीमा शुल्क द्वारा संशोधन किया गया है, जिसमें नियम 2(घक) तथा नियम 22 का स्पष्टीकरण निम्नलिखित प्रावधान शामिल करते हुए जोड़ा गया है:

"जांच की अवधि:-

- (i) जांच की शुरुआत की तारीख को छः माह पुरानी से अधिक नहीं होगी।
- (ii) बारह माह की अवधि के लिए होगी तथा लिखित में रिकार्ड किए जाने वाले कारणों से निर्दिष्ट प्राधिकारी न्यूनतम 6 माह अथवा अधिकतम 18 माह पर विचार कर सकते हैं।"

यह नोट किया जाता है कि उपर्युक्त संशोधन वर्तमान जांच की शुरुआत के बाद किए गए हैं। फिर भी प्राधिकारी ने ऊपर किए गए उल्लेख के अनुसार जांच की अवधि के रूप में अप्रैल, 2019 से सितंबर, 2019 (6 माह) के चयन के लिए आवेदक द्वारा दिए गए औचित्य पर विधिवत विचार किया था।

- ख. जहां तक वार्षिक रिपोर्ट में सूचित लगभग 1 माह की बंदी का संबंध है जिसके परिणामस्वरूप जांच की अवधि केवल 5 माह तक प्रभावी रूप से कम की गई, यह नोट किया जाता है कि संयंत्र का रख-रखाव वर्ष 2018-19 में किया गया था न कि अप्रैल, 2019 से सितंबर, 2019 की अवधि में। अतः जांच की अवधि स्पष्ट 6 माह से संबंधित है और दी गई परिस्थितियों में उपयुक्त पाई जाती है।
- ग. प्राधिकारी नोट करते हैं कि देश में मांग-आपूर्ति अंतराल से पाटित आयातों से समाधान की मांग करने से किसी घरेलू उद्योग को नहीं रोकता। डीएसएमआई डेमिस्तु लिमिटेड बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी के मामले में



सेसटेट द्वारा माने गए अनुसार मांग-आपूर्ति अंतराल पाटन का औचित्य नहीं बनाता। विदेशी उत्पादक हमेशा अपाटित कीमतों पर उत्पाद की बिक्री कर भारतीय मांग को पूरा कर सकते हैं। पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के बाद भी देश में आयात प्रतिबंधित नहीं होते हैं। अतः इस दावे के लिए कोई आधार नहीं है कि पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने से निचले स्तर के उद्योग के लिए कच्ची सामग्री की कमी हो सकती है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने से एक उचित व्यापारिक क्षेत्र बनता है और बाजार में उचित प्रतिस्पर्धा नहीं रुकती। प्राधिकारी घरेलू उद्योग के अनुरोध को भी नोट करते हैं कि एनिलिन का निर्यात कई देशों द्वारा किया जाता है। प्रयोक्ता किसी भी स्रोत से संबद्ध सामानों के आयात करने के लिए स्वतंत्र हैं।

घ. प्राधिकारी नोट करते हैं कि वर्तमान जांच एनिलिन के लिए है न कि उसके निचले स्तर के उत्पाद के लिए। एनिलिन के निचले स्तर के उत्पाद का आयात वर्तमान मामले को प्रभावित नहीं करता।

ङ. प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच आवेदक द्वारा प्रस्तुत पर्याप्त प्रथम दृष्टया साक्ष्य के आधार पर शुरू की गई थी।

### च. सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन का निर्धारण

23. धारा 9क(1)(ग) के अधीन, किसी वस्तु के संबंध में सामान्य मूल्य का तात्पर्य है:

(i) व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में समान वस्तु की तुलनीय कीमत जब वह उप नियम (6) के तहत बनाए गए नियमों के अनुसार यथानिर्धारित निर्यातक देश या क्षेत्र में खपत के लिए नियत हो, अथवा

(ii) जब निर्यातक देश या क्षेत्र के घरेलू बाजार में व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में समान वस्तु की कोई बिक्री न हुई हो अथवा जब निर्यातक देश या क्षेत्र की बाजार विशेष की स्थिति अथवा उसके घरेलू बाजार में कम बिक्री मात्रा के कारण ऐसी बिक्री की उचित तुलना न हो सकती हो तो सामान्य मूल्य निम्नलिखित में से कोई एक होगा:-

(क) समान वस्तु की तुलनीय प्रतिनिधिक कीमत जब उसका निर्यात उप-धारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार निर्यातक देश या क्षेत्र से या किसी उचित तीसरे देश से किया गया हो; अथवा उपधारा- (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार यथानिर्धारित प्रशासनिक, बिक्री और सामान्य लागत एवं लाभ हेतु उचित वृद्धि के साथ उद्गम वाले देश में उक्त वस्तु की उत्पादन लागत;

(ख) परंतु यदि उक्त वस्तु का आयात उद्गम वाले देश से भिन्न किसी देश से किया गया है और जहां उक्त वस्तु को निर्यात के देश से होकर केवल यानांतरण किया गया है अथवा ऐसी वस्तु का उत्पादन निर्यात के देश में नहीं होता है, अथवा निर्यात के देश में कोई तुलनीय कीमत नहीं है, वहां सामान्य मूल्य का निर्धारण उद्गम वाले देश में उसकी कीमत के संदर्भ में किया जाएगा।

### च.1 घरेलू उद्योग के अनुरोध

24. सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

क. चीनी उत्पादकों का सामान्य मूल्य तब स्वीकार नहीं किया जा सकता जब तक उत्पादक यह न दर्शाएं कि उनके खाते नियमावली के नियम 7 और 8 के प्रावधानों, चीनी अभिगम नयाचार के प्रावधानों और निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा अपनाई जा रही परिपाटी को ध्यान में रखते हुए विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन और बिक्री से जुड़ी लागतें उपयुक्त रूप से दर्शाते हैं।

ख. सामान्य मूल्य प्रतिनिधि देश के आधार पर निर्धारित किए जाने की आवश्यकता है।

ग. चीन और यूरोपीय संघ को छोड़कर, अन्य देशों में संबद्ध सामानों के उत्पादकों की संख्या बहुत कम है।

घ. यूरोपीय संघ में उत्पादन क्षमता लगभग चीन के ही स्तर पर है।

ङ. केवल यूरोपीय संघ से निर्यात भारत के निर्यातों के 5 प्रतिशत से अधिक हैं।

- च. जीडीपी और जीएनआई की तुलना करने पर भी, यूरोपीय संघ को छोड़कर कोई ऐसा देश नहीं है जिसे उपयुक्त प्रतिनिधि देश माना जा सके।
- छ. यूरोपीय संघ को सामान्य मूल्य के निर्धारण के प्रयोजन के लिए उपयुक्त प्रतिनिधि देश माना जा सकता है।
- ज. बेल्जियम से जर्मनी को निर्यात बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में एनिलिन की कीमत का साक्ष्य हैं।
- झ. पाटन मार्जिन सकारात्मक और काफी है।

## च.2 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

25. सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन के संबंध में हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

- i. सामान्य मूल्य बेल्जियम से जर्मनी को बिक्री कीमत के आधार पर नहीं अपनाया जा सकता क्योंकि वह नियम 7 – दूसरे विकल्प की अपेक्षा को पूरा नहीं करता। एक विकल्प सामान्य मूल्य के आधार के रूप में भारत सहित बेल्जियम से दूसरे देशों को कीमत हो सकती है।
- ii. बेल्जियम से जर्मनी को कीमत अंतःदेशीय कीमत है और यूरोपीय संघ में कीमत के रूप में नहीं देखी जा सकती। मानी गई कीमत यूरोपीय संघ में विद्यमान कीमतों की तुलना में बहुत अधिक है।
- iii. यूरोपीय संघ को प्रतिनिधि देश के रूप में मानना उपयुक्त नहीं है। याचिकाकर्ता कानूनी रूप से अनुमति के अनुसार उचित दावे करने में विफल रहा है।
- iv. प्राधिकारी से अनुरोध है कि वे यह मानते हुए सामान्य मूल्य के संबंध में याचिकाकर्ता के विभिन्न प्रस्तावों पर पुनः विचार करें कि चीनी उत्पादक बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियों को पूरा करने में सक्षम नहीं हो सकते हैं।
- v. प्राधिकारी ने बाजार अर्थव्यवस्था के संबंध में निर्यातकों से भारी मात्रा में सूचना की मांग करते हुए चीन जन. गण. से पृथक प्रश्नावली दायर की हैं।
- vi. भारत को डब्ल्यूटीओ में अपने दायित्व को पूरा करना चाहिए और चीन जन. गण. को बाजार अर्थव्यवस्था स्तर की मान्यता देनी चाहिए। चीन जन. गण. के लिए प्रतिनिधि देश का सिद्धांत 11 दिसंबर, 2016 से समाप्त हो गया। डब्ल्यूटीओ में चीनी अभिगम की समाप्ति के बाद उसे उसी तरह माना जाना चाहिए जैसा किसी अन्य डब्ल्यूटीओ सदस्य को माना जाता है और किसी सदस्य विशेष के घरेलू कानून को ध्यान में न रखते हुए चीन जन. गण. से आयात चीनी कीमतों और लागतों के आधार पर प्रदर्शित किए जाने चाहिए।
- vii. यूरोपीय संघ में, अधिकतर एनिलिन उत्पादक एमडीआई विनिर्माता भी हैं। कोवेस्ट्रो का बेल्जियम और जर्मनी में अभिगम संयंत्र और जर्मनी तथा स्पेन में एमडीआई संयंत्र है। कोवेस्ट्रो को एमडीआई विनिर्माण के लिए बेल्जियम से जर्मनी तथा स्पेन को एनिलिन स्थानांतरित करना होता है। यह स्थानांतरण कीमत बाजार कीमत नहीं माना जाएगी क्योंकि एनिलिन का स्थानांतरण संबद्ध पक्षकारों के बीच कोवेस्ट्रो समूह के भीतर किया जाता है। यही स्थिति सीयूएफ को छोड़कर बीएएसएफ, डीओडब्ल्यू, हंट्समैन और बोरसोचैम पर लागू होती है। सामान्य मूल्य संबद्ध कंपनियों के बीच लेन-देनों के आधार पर नहीं माना जा सकता।
- viii. सीयूएफ, यूरोपीय संघ में एनिलिन का एक मात्र उत्पादक है जिसके पास एमडीआई संयंत्र नहीं है। अतः एनिलिन का स्थानांतरण सीयूएफ तथा उन संबद्ध पक्षकारों के भीतर नहीं किया जा सकता जो कि कोवेस्ट्रो, बीएएसएफ, डीओडब्ल्यू, हंट्समैन और बोरसोचैम के असमान विभिन्न देशों में स्थित हो सकते हैं। सीयूएफ संयंत्र केवल पुर्तगाल में स्थित है। सामान्य मूल्य के प्रयोजन के लिए पुर्तगाल द्वारा जर्मनी को सीयूएफ (उत्पादक) की बिक्री पर सबसे अधिक विश्वास किया जा सकता है।
- ix. मानक प्रचालन प्रक्रिया (एसओपी) की पुस्तिका के पैरा 13.18.2 में यह उल्लेख है कि उपयुक्त प्रतिनिधि देश पर देश के विकास और विचाराधीन उत्पाद के स्तर पर विचार करने के बाद विश्वास किया जा सकता है।

- x. जीडीपी – प्रति व्यक्ति आय, जीडीपी, जीडीपी प्रति व्यक्ति, उपभोक्ता खर्च, जीडीपी वास्तविक वृद्धि दर, अर्थव्यवस्था वृद्धि दर, अर्थव्यवस्था वृद्धि, विश्व व्यापार वृद्धि और दो देशों के बीच जनसंख्या में भारी अंतर है और इसीलिए वे तुलनीय नहीं हैं।
- xi. याचिका में प्रस्तुत आंकड़ों के आधार पर भारत में चीन जन. गण. और यूरोपीय संघ से आयातों की मात्रा और कीमत के बीच भारी अंतर है।
- xii. यदि प्राधिकारी इन अनुरोधों से सहमत नहीं हैं कि पुर्तगाल से जर्मनी को कीमतों को सामान्य मूल्य के रूप में माना जाना चाहिए तो फिर यह अनुरोध है कि चीन जन. गण. के लिए सामान्य मूल्य नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 7 के अनुसार निर्मित किया जा सकता है। इस प्रयोजन के लिए बेनजेन की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों पर विचार किया जा सकता है, कच्ची सामग्री के खपत कारक पर प्रतिभागी उत्पादक के लिए विचार किया जा सकता है, चीन में विद्यमान कीमतों से यूटिलिटीयों की लागत निकाली जा सकती है और चीन सहित अंतर्राष्ट्रीय बाजार में विद्यमान ब्याज दर पर विचार किया जा सकता है। चीन जन. गण. से भारत को निर्यातित विचाराधीन उत्पाद के लिए उपयुक्त लाभ भी जोड़ा जा सकता है।

### च.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

#### च.3.1 सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत का निर्धारण

##### चीनी उत्पादकों के लिए बाजार अर्थव्यवस्था स्थिति

26. चाइनीज एसेसन प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 15 में निम्नलिखित प्रावधान है: "जीएटीटी का अनुच्छेद-VI, टैरिफ और व्यापार पर सामान्य समझौता, 1994 ("पाटनरोधी समझौता") के अनुच्छेद-VI के कार्यान्वयन पर समझौता तथा एससीएम समझौता निम्नलिखित के अनुरूप डब्ल्यूटीओ सदस्यों में चीन मूल के आयातों वाली कार्यवाहियों पर लागू होंगे:

- (क) जीएटीटी के अनुच्छेद-VI और पाटनरोधी समझौते के तहत मूल्य की तुलना का निर्धारण करने में आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य या तो जांचाधीन उद्योग के लिए चीन के मूल्यों अथवा लागतों का उपयोग करेंगे या उस पद्धति को उपयोग करेंगे जो निम्नलिखित के आधार पर चीन में घरेलू मूल्यों अथवा लागतों के साथ सख्ती से तुलना करने में आधारित नहीं है:
  - (i) यदि जांचाधीन उत्पादक साफ-साफ यह दिखा सकते हैं कि समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले उद्योग में उस उत्पाद के विनिर्माण, उत्पादन और बिक्री के संबंध में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां रहती हैं तो निर्यात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य मूल्य की तुलनीयता का निर्धारण करने में जांचाधीन उद्योग के लिए चीन के मूल्यों अथवा लागतों का उपयोग करेगा।
  - (ii) आयातक डब्ल्यूटीओ सदस्य उस पद्धति का उपयोग कर सकता है जो चीन में घरेलू कीमतों अथवा लागतों के साथ सख्त अनुपालन पर आधारित नहीं है, यदि जांचाधीन उत्पादक साफ-साफ यह नहीं दिखा सकते हैं कि उस उत्पाद के विनिर्माण, उत्पादन और बिक्री के संबंध में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले उद्योग हैं।
- (ख) एससीएम समझौते के पैरा II, III और V के अंतर्गत कार्यवाहियों में अनुच्छेद 14(क), 14(ख), 14(ग) और 14(घ) में निर्धारित राजसहायता को बताते समय एससीएम समझौते के प्रासंगिक प्रावधान लागू होंगे, तथापि, उसके प्रयोग करने में यदि विशेष कठिनाईयां हों, तो आयात करने वाले डब्ल्यूटीओ सदस्य राजसहायता लाभ की पहचान करने और उसको मापने के लिए तब पद्धति का उपयोग कर सकते हैं जिसमें उस संभावना को ध्यान में रखती है और चीन में प्रचलित निबंधन और शर्तें उपयुक्त बेंचमार्क के रूप में सदैव उपलब्ध नहीं हो सकती हैं। ऐसी पद्धतियों को लागू करने में, जहां व्यवहार्य हो, आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य के द्वारा चीन से बाहर प्रचलित निबंधन और शर्तों का उपयोग के बारे में विचार करने से पूर्व ऐसी विद्यमान निबंधन और शर्तों को ठीक करना चाहिए।

- (ग) आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य उप-पैरा (क) के अनुसार प्रयुक्त पद्धतियों को पाटनरोधी कार्य समिति के लिए अधिसूचित करेगा तथा उप पैराग्राफ (ख) के अनुसार प्रयुक्त पद्धतियों को कमिटी ऑन सब्सिडीज और काउंटर वेलिंग मैसर्स के लिए अधिसूचित करेगा।
- (घ) आयात करने वाले डब्ल्यूटीओ सदस्य को राष्ट्रीय कानून के तहत चीन ने एक बार यह सुनिश्चित कर लिया है कि यह एक बाजार अर्थव्यवस्था है, तो उप पैराग्राफ के प्रावधान (क) समाप्त कर दिए जाएंगे, बशर्ते आयात करने वाले सदस्य के राष्ट्रीय कानून में प्राप्ति की तारीख के अनुरूप बाजार अर्थव्यवस्था संबंधी मानदंड हो। किसी भी स्थिति में उप पैराग्राफ (क)(ii) के प्रावधान प्राप्ति की तारीख के बाद 15 वर्षों में समाप्त होंगे। इसके अलावा, आयात करने वाले डब्ल्यूटीओ सदस्य के राष्ट्रीय कानून के अनुसरण में चीन के द्वारा यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां एक विशेष उद्योग अथवा क्षेत्र में प्रचलित हैं, उप पैराग्राफ (क) के गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के प्रावधान उस उद्योग अथवा क्षेत्र के लिए लागू नहीं होंगे।"

27. यह नोट किया जाता है कि यद्यपि अनुच्छेद 15(क)(ii) में निहित प्रावधान 11.12.2016 को समाप्त हो गया है, तथापि अभिगम नयाचार के 15(क)(i) के तहत दायित्वों के साथ पठित डब्ल्यूटीओ के अनुच्छेद 2.2.1.1 के अंतर्गत प्रावधान बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार के स्तर का दावा करने के संबंध में पूरक प्रश्नावली में दी जाने वाली सूचना/आंकड़ों के माध्यम से पूरा किए जाने के लिए पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 8 में निर्धारित मानदंड की अपेक्षा है। यह नोट किया जाता है कि चूंकि चीन जन. गण. से किसी भी उत्तरदाता उत्पादक तथा निर्यातक ने पूरक प्रश्नावली के उत्तर प्रस्तुत नहीं किए हैं, अतः सामान्य मूल्य का परिकलन नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 7 के प्रावधानों के अनुसार किया जाना अपेक्षित है।

28. तदनुसार, संबद्ध देश से सभी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य तथा निर्यात कीमत निम्नलिखित रूप में निर्धारित की गई है।

#### **चीन जन. गण. में सभी उत्पादकों के लिए सामान्य मूल्य**

29. चूंकि, चीन जन. गण. से किसी भी उत्पादक ने अपने आंकड़ों/सूचना के आधार पर सामान्य मूल्य के निर्धारण का दावा नहीं किया है, अतः सामान्य मूल्य नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 7 के अनुसार निर्धारित किया गया है जो निम्नलिखित रूप में पठित है:

"गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाले देशों से आयात के मामले में, उचित लाभ मार्जिन को शामिल करने के लिए भारत में समान उत्पाद के लिए वास्तविक रूप से भुगतान किया गया अथवा भुगतान योग्य, आवश्यकतानुसार पूर्णतया समायोजित कीमत रहित, सामान्य, मूल्य का निर्धारण तीसरे देश के बाजार अर्थव्यवस्था में कीमत अथवा परिकलित मूल्य के आधार पर अथवा भारत सहित ऐसे किसी तीसरे देश से अन्य देशों के लिए कीमत अथवा जहां यह संभव नहीं है, या किसी अन्य उचित आधार पर किया जाएगा। संबद्ध देश के विकास के स्तर तथा संबद्ध उत्पाद को देखते हुए निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा यथोचित पद्धति द्वारा एक समुचित बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश का चयन किया जाएगा और चयन के समय पर उपलब्ध कराई गई किसी विश्वसनीय सूचना पर यथोचित रूप से विचार किया जाएगा। बाजार अर्थव्यवस्था वाले किसी अन्य तीसरे देश के संबंध में किसी समयानुरूपी मामले में की जाने वाली जांच के मामले में जहां उचित हों, समय-सीमा के भीतर कार्रवाई की जाएगी। जांच से संबंधित पक्षकारों को किसी अनुचित विलंब के बिना बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश के चयन के विशेष में सूचित किया जाएगा और अपनी टिप्पणियां देने के लिए एक समुचित समयावधि प्रदान की जाएगी।"

30. प्राधिकारी ने चीन के लिए प्रतिनिधि देश के रूप में यूरोपीय संघ के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों से टिप्पणियां मांगी हैं। जांच की शुरुआत की अधिसूचना का उद्धरण निम्नलिखित है:

9. सभी हितबद्ध पक्षकारों को सलाह दी जाती है कि वे जांच की शुरुआत की अधिसूचना जारी किए जाने की तारीख से 30 दिनों के भीतर इस मुद्दे पर अपनी टिप्पणियां दें। इस जांच के लिए चीन के लिए प्रतिनिधि देश के रूप में यूरोपीय संघ के दावे पृष्ठ 6 के 3 की विस्तृत जांच होने तक वर्तमान जांच की शुरुआत के प्रयोजन के लिए प्राधिकारी ने चीन जन. गण. का सामान्य मूल्य निर्धारित करने के लिए बेल्जियम से जर्मनी को बिक्री कीमत ली है।

31. चीन के लिए प्रतिनिधि देश के रूप में यूरोपीय संघ के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों की टिप्पणियों के संबंध में यह नोट किया जाता है कि जांच की शुरुआत में प्राधिकारी द्वारा दी गई 30 दिनों की समय सीमा के भीतर किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने चीन के लिए एक प्रतिनिधि देश के रूप में यूरोपीय संघ को मानने के प्रस्ताव पर अपनी टिप्पणियां नहीं दीं। तथापि, डाईस्टफ्स मैनुफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (डीएमएआई) और वनहुआ ग्रुप ने दी गई समयावधि के बाद प्रस्तावित सिद्धांत पर चिंताएं उठाई हैं।

32. एक हितबद्ध पक्षकार ने यह तर्क दिया है कि इस मामले में सामान्य मूल्य भारत में विधिवत समायोजित प्रदत्त अथवा देय कीमत के आधार पर निर्धारित किया जाना चाहिए।

33. चूंकि उपयुक्त बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश के रूप में यूरोपीय संघ को मानने विरोधी अनुरोध हैं, अतः प्राथमिक जांच परिणामों के प्रयोजन के लिए सामान्य मूल्य लाभ शामिल करने के लिए विधिवत समायोजित भारत में प्रदत्त अथवा देय कीमत के आधार पर निर्धारित किया गया है जिसे बिक्री, सामान्य एवं प्रशासनिक व्यय तथा उपयुक्त लाभ के लिए जोड़ने के बाद भारत में उत्पादन लागत पर विचार करते हुए निर्धारित किया गया है। इस प्रकार निर्धारित सामान्य मूल्य पाटन मार्जिन तालिका में नीचे दिया गया है।

### निर्यात कीमत का निर्धारण

**मैसर्स वनहुआ केमिकल ग्रुप कं. लिमिटेड, मैसर्स वनहुआ केमिकल (हांगकांग) कं. और मैसर्स केम्पर एनर्जी पीटीई. लिमिटेड, सिंगापुर**

34. प्राधिकारी नोट करते हैं कि निम्नलिखित उत्पादकों/निर्यातकों ने प्रश्नावली का उत्तर दायर किया है:

- i. मैसर्स वनहुआ केमिकल ग्रुप कं. लिमिटेड (वनहुआ)
- ii. मैसर्स वनहुआ केमिकल (हांगकांग) कं. लिमिटेड, हांगकांग
- iii. मैसर्स केम्पर एनर्जी पीटीई. लिमिटेड, सिंगापुर
- iv. मैसर्स वनहुआ केमिकल (यंताई) ट्रेडिंग कं. लिमिटेड
- v. मैसर्स वनहुआ केमिकल (निंगबो) कं. लिमिटेड
- vi. मैसर्स वनहुआ केमिकल (निंगबो) ट्रेडिंग कं. लिमिटेड

35. यह नोट किया जाता है कि जांच की अवधि के दौरान, मैसर्स वनहुआ केमिकल ग्रुप कं. लि. (उत्पादक/निर्यातक) चीन जन. गण. में संबद्ध सामानों का उत्पादक है और उसने भारत में ग्राहकों को संबद्ध तथा असंबद्ध व्यापारियों के माध्यम से संबद्ध सामानों का निर्यात किया है। उत्तरदाता उत्पादक/निर्यातक ने निर्यातक प्रश्नावली के उत्तर के परिशिष्ट-3ग में भारत को संबद्ध सामानों के निर्यातों के ब्यौरे दिए हैं। उत्तरदाता उत्पादक/निर्यातक ने यह भी स्पष्ट किया है कि उनके मामले में परिशिष्ट-3क लागू नहीं है क्योंकि भारतीय ग्राहकों को कोई सीधी बिक्री नहीं है। उत्तर से यह नोट किया जाता है कि मैसर्स वनहुआ केमिकल ग्रुप कं. लि. ने मैसर्स वनहुआ केमिकल (हांगकांग) कं. लि., हांगकांग (व्यापारी) के माध्यम से भारत को \*\*\*\* मी. टन संबद्ध सामानों का निर्यात किया है। मैसर्स वनहुआ केमिकल (हांगकांग) कं. लि., हांगकांग ने बदले में मैसर्स केम्पर एनर्जी पीटीई. लि., सिंगापुर के माध्यम से भारत को उसी का निर्यात किया है। अन्य संबद्ध उत्पादक मैसर्स वनहुआ केमिकल (निंगबो) कं. लि. ने जांच की अवधि के दौरान सीधे ही अपने संबद्ध व्यापारी के माध्यम से भारत को संबद्ध सामानों का निर्यात नहीं किया है। यह भी नोट किया जाता है कि मैसर्स वनहुआ केमिकल (निंगबो) कं. लि., मैसर्स वनहुआ केमिकल (यंताई) ट्रेडिंग कं. लि. और मैसर्स वनहुआ केमिकल (निंगबो) ट्रेडिंग कं. लि. भारत को निर्यातों में शामिल नहीं हैं।

36. भारत को निर्यातों के लिए उत्पादक/निर्यातक ने पत्तन तथा अन्य संबद्ध व्यय, पोत के माध्यम से परिवहन तथा गैर-वापसी योग्य वैट के निमित्त समायोजनों का दावा किया है। इसके अतिरिक्त, संबद्ध निर्यातक मैसर्स वनहुआ केमिकल (हांगकांग) कं. लि., हांगकांग द्वारा दावा किए गए बैंक प्रभार तथा ऋण व्यय पर कारखानागत निर्यात कीमत निकालने के लिए भी अनंतिम रूप से विचार किया गया है। प्राधिकारी ने सूचना के सत्यापन के अध्यधीन प्राथमिक जांच परिणामों के प्रयोजन के लिए उत्पादक/निर्यातक द्वारा दायर प्रश्नावली के उत्तर में दिए गए निर्यातों के ब्यौरों पर विश्वास किया है। पत्तन एवं अन्य संबद्ध व्यय, पोत से परिवहन और गैर-वापसी योग्य वैट, बैंक प्रभार तथा



व्यापारी से ऋण व्यय के निमित्त समायोजन प्राथमिक जांच परिणामों के प्रयोजन के लिए अनंतिम रूप से स्वीकार किए गए हैं। तदनुसार, प्राधिकारी ने निम्नलिखित पाटन मार्जिन तालिका में उल्लिखितानुसार अनंतिम रूप से निवल निर्यात कीमत निर्धारित की है।

**चीन जन. गण. से अन्य सभी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए**

37. जिन अन्य उत्पादकों/निर्यातकों ने वर्तमान जांच में भाग नहीं लिया है, उन सभी के लिए निर्धारित कीमत समुद्री भाड़ा, समुद्री बीमा, ऋण लागत, अंतर्देशीय तथा पत्तन प्रभार और वैट वापसी के लिए उचित समायोजन की अनुमति देने के बाद विस्तार करते हुए उपलब्ध तथ्यों के अनुसार निर्धारित की गई है और वह पाटन मार्जिन तालिका में उल्लिखित की गई है।

**च.3.2 पाटन मार्जिन**

38. संबद्ध सामानों के लिए सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत पर विचार करते हुए पाटन मार्जिन निम्नलिखित रूप में अनंतिम रूप से निर्धारित किया गया है:

देश	उत्पादक का नाम	सामान्य मूल्य/ सीएनवी (अमेरिकी डॉलर/मी. टन)	निर्यात कीमत (अमेरिकी डॉलर/मी. टन)	पाटन मार्जिन अमेरिकी डॉलर/मी. टन	पाटन मार्जिन %	पाटन मार्जिन रेंज
चीन जन. गण.	वनहुआ केमिकल ग्रुप कं. लि.	****	****	****	****	20-40
	अन्य उत्पादक	****	****	****	****	40-60

**छ. क्षति एवं कारणात्मक संपर्क**

**छ.1 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध**

39. क्षति और कारणात्मक संपर्क के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

- संबद्ध सामानों की मांग में जांच की अवधि में गिरावट आई है। तथापि, मांग फिर भी क्षमता से अधिक है और इसीलिए गिरावट घरेलू उद्योग को क्षति नहीं पहुँचा सकती।
- संबद्ध सामानों के आयात पूर्ण दृष्टि से और उत्पादन तथा खपत के संबंध में संबद्ध देश से काफी बढ़े हैं।
- आयात कीमतों में जांच की अवधि में तेजी से गिरावट आई है।
- संबद्ध आयात घरेलू उद्योग की कीमतों की कटौती कर रहे हैं।
- घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत में गिरावट आई है जबकि घरेलू उद्योग की बिक्री लागत बढ़ी है।
- आयातों ने घरेलू उद्योग की कीमतों का ह्रास किया है।
- घरेलू उद्योग का क्षमता उपयोग कम है।
- घरेलू उद्योग के उत्पादन और बिक्री में आधार वर्ष की तुलना में 51 प्रतिशत और 43 प्रतिशत से अधिक की गिरावट देखी है।
- घरेलू उद्योग की लाभप्रदता जांच की अवधि में गंभीर रूप से प्रभावित हुई है क्योंकि वह हानियों में चल रही है।
- घरेलू उद्योग का नकद लाभ तथा निवेश पर आय जांच की अवधि में नकारात्मक हुई है।



- ट. घरेलू उद्योग ने क्षति की अवधि में अपना लगभग 28 प्रतिशत बाजार हिस्सा खोया है। संबद्ध देश के आयातों के बाजार हिस्से में लगभग 46 प्रतिशत से 78 प्रतिशत तक वृद्धि ली है।
- ठ. घरेलू उद्योग में औसत मालसूची काफी है जो वार्षिक बिक्री मूल्य का लगभग \*\*\*\* प्रतिशत दर्शाती है।
- ड. घरेलू उद्योग ने सभी मानदंडों में नकारात्मक वृद्धि दर्ज की है।
- ढ. संबद्ध आयात चिंताजनक दर पर बढ़े हैं जो और भी अधिक क्षति का खतरा पैदा कर रहे हैं।
- ण. संबद्ध देश में उत्पादकों के पास काफी क्षमताएं हैं।
- त. आयातों का घरेलू उद्योग की कीमतों पर ह्रासमान प्रभाव रहा है और संबद्ध आयातों की मांग में वृद्धि के लिए उनका रास्ता बनाने की संभावना है।

## छ.2 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

40. क्षति के संबंध में हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध निम्नलिखित हैं:
  - क. जब कीमत कटौती उच्चतम स्तर पर थी तो घरेलू उद्योग बहुत अच्छा लाभ कमा रहा था। तथापि, जब कीमत कटौती न्यूनतम स्तर पर है तो उसे हानियां हुई हैं।
  - ख. लगभग 70,000-75,000 मी. टन संबद्ध सामान का आयात किया जाता है क्योंकि भारत में उत्पादन क्षमता भारत में मांग से कम है।
  - ग. आयात चीन से किए जाते हैं क्योंकि किफायत के कारण वे सबसे अधिक प्रतिस्पर्द्धी कीमत वाले हैं।
  - घ. वस्तुतः घरेलू उद्योग उस समय अधिक लाभ प्राप्त कर रहा था जब कीमत कटौती आधार वर्ष में 10-20 प्रतिशत थी और जब जांच की अवधि में वह 0-10 प्रतिशत थी तब उसे हानियां हुईं जो जांच की अवधि में 12 माह से कम होने के कारण ह्रास दर्शाता है।
  - ड. जांच की अवधि में कम से कम 2 माह के लिए कीमत कटौती नकारात्मक थी जो यह दर्शाती है कि आयातों की पहुँच कीमत क्षति का कारक नहीं है और हानियां आयातों के दबाव के कारण नहीं हो सकतीं।
  - च. घरेलू उद्योग 2018-19 में लगभग 108 प्रतिशत और जांच की अवधि में 119 प्रतिशत क्षमता उपयोग पर प्रचालन कर रहा था। गिरावट के बाद भी वह बहुत उपयुक्त स्तर पर होता। इसके अतिरिक्त, विगत उच्च संख्याओं से थोड़ा सा संशोधन क्षति बताने वाली स्थिति नहीं है।
  - छ. आर्थिक मंदी, कच्चे तेल पर आधारित इनपुट लागत में उतार-चढ़ाव आदि के कारण कीमतों में अस्थायी संचलनों को अगले पांच वर्षों के लिए पाटनरोधी शुल्क लगाने हेतु क्षति नहीं कहा जा सकता।
  - ज. क्षति स्व-प्रभावित हो सकती है और घरेलू उद्योग की बंदी के कारण हो सकती है।
  - झ. जांच की अवधि के दौरान आर्थिक प्रवृत्ति में अकस्मात गिरावट आंकड़ों के संबंध में गंभीर प्रश्न उठाती है क्योंकि 2016-17 से 2018-19 के बीच क्षति की अवधि में सभी कुछ सामान्य था।
  - ञ. आधार वर्ष की तुलना में जांच की अवधि में घरेलू बिक्री (43 प्रतिशत) और निर्यात बिक्री (33 प्रतिशत) दोनों में गिरावट है जो यह दर्शाता है कि क्षति किसी अन्य कारण से हो सकती है।
  - ट. बिक्री लागत में वृद्धि और बिक्री कीमत में गिरावट कम उत्पादन और क्षमता उपयोग के कारण है न कि संबद्ध देश से आयातों के कारण।
  - ठ. करार के अनुच्छेद 3.5 में प्राधिकारी के लिए यह अपेक्षित है कि वे क्षति पहुँचाने वाले पाटन को छोड़कर अन्य कारकों की जांच करें।
  - ड. यूएस हॉट रोलड स्टील में अपीलीय निकाय ने यह माना है कि यूएस नॉर्वेजियन सलमन एंडी में पैनल द्वारा जांच त्रुटिपूर्ण थी (यूएस अटलांटिक में पैनल में माना था कि अन्य कारकों के कारण क्षति को अलग करने की कोई आवश्यकता नहीं है)।
  - ढ. याचिका उन कई मुद्दों को हल करने में विफल रहती है जिनका घरेलू उद्योग के निष्पादन पर प्रभाव है।

**छ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच**

41. अनुबंध-II के साथ पठित नियमावली के नियम 11 में यह प्रावधान है कि क्षति के निर्धारण में "... पाटित आयातों की मात्रा, समान वस्तुओं के लिए घरेलू बाजार में कीमतों पर उनके प्रभाव और ऐसी वस्तुओं के घरेलू उत्पादकों पर इस प्रकार के आयातों का परिणामी प्रभाव सहित सभी संगत तथ्यों पर विचार करते हुए ..." घरेलू उद्योग को क्षति दर्शाने वाले कारकों की जांच शामिल होगी। कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए, इस बात की जांच करना आवश्यक माना गया है कि क्या भारत में समान वस्तु की कीमत की तुलना में पाटित आयातों द्वारा कीमत में बहुत अधिक कटौती हुई है अथवा यह कि क्या इस प्रकार के आयातों के प्रभाव से अन्यथा कीमतों का बहुत अधिक मात्रा में हास हुआ है अथवा कीमत में वृद्धि रूक जाती जो अन्यथा बहुत अधिक मात्रा में हुई होती। भारत में घरेलू उद्योगों पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच करने के लिए, इन सूचकांकों जिनका उद्योग की स्थिति पर प्रभाव पड़ता हो जैसे उत्पादन, क्षमता का उपयोग, बिक्री की मात्रा, मालसूची, लाभप्रदता, निवल बिक्री प्राप्ति, पाटन की मात्रा और मार्जिन आदि पर विचार नियमावली के अनुबंध-II के अनुसार किया गया है।

**छ.3.1 घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों का मात्रात्मक प्रभाव****क. मांग का मूल्यांकन/स्पष्ट खपत**

42. वर्तमान जांच के प्रयोजन के लिए प्राधिकारी ने भारत में उत्पाद की मांग अथवा स्पष्ट खपत पर भारतीय उत्पादकों की घरेलू बिक्री और सभी स्रोतों से आयातों की मात्रा के रूप में विचार किया है।

क्र. सं.	विवरण	यूनिट	2016-17	2017-18	2018-19	जांच की अवधि	
						वास्तविक	वार्षिकीकृत
1	घरेलू उद्योग की बिक्री	मी. टन	41,604	41,339	34,813	11,952	23,904
2	प्रवृत्ति	सूचकांक	100	99	84	57	57
3	संबद्ध देश	मी. टन	40,523	48,918	66,748	46,767	93,534
4	प्रवृत्ति	सूचकांक	100	121	165	231	231
5	अन्य देशों के आयात	मी. टन	4,127	16,441	21,370	823	1,645
6	प्रवृत्ति	सूचकांक	100	398	518	40	40
7	कुल मांग	मी. टन	86,253	1,06,697	1,22,931	59,542	1,19,083
8	प्रवृत्ति	सूचकांक	100	124	143	138	138

43. संबद्ध सामानों के लिए मांग जांच की अवधि में आंशिक गिरावट के साथ क्षति की अवधि में बढ़ी है।

**ख. पूर्ण दृष्टि से और सापेक्ष दृष्टि से संबद्ध देश से आयातों में वृद्धि**

44. आयातों की मात्रा के संबंध में, प्राधिकारी के लिए यह विचार करना अपेक्षित है कि क्या पूर्ण दृष्टि से अथवा भारत में उत्पादन अथवा खपत के संबंध में आयातों में काफी वृद्धि हुई है। वास्तविक स्थिति निम्नलिखितानुसार है:

क्र. सं.	विवरण	यूनिट	2016-17	2017-18	2018-19	जांच की अवधि	
						वास्तविक	वार्षिकीकृत
1	चीन जन. गण. से आयात	मी. टन	40,523	48,918	66,748	46,767	93,534
2	अन्य देशों से आयात	मी. टन	4,127	16,441	21,370	823	1,645
3	कुल आयात	मी. टन	44,650	65,358	88,118	47,590	95,179

4	के संबंध में संबद्ध आयात						
क	कुल आयात	%	91%	75%	76%	98%	98%
ख	भारतीय उत्पादन	%	****	****	****	****	****
ग	प्रवृत्ति	सूचकांक	100	119	180	472	472
घ	भारतीय मांग	%	47%	46%	54%	79%	79%
ङ	प्रवृत्ति	सूचकांक	100	98	116	167	167

45. यह नोट किया जाता है कि संबद्ध आयात क्षति की अवधि में पूर्ण दृष्टि से काफी बढ़े हैं। संबद्ध आयात सापेक्ष दृष्टि से भी बढ़े हैं। आयात कुल आयातों, भारत में उत्पादन एवं खपत के संबंध में बढ़े हैं। इसके अतिरिक्त, आयात आधार वर्ष और तत्काल पूर्व वर्ष, दोनों की तुलना में वृद्धि दर्शाते हैं। यह भी नोट किया जाता है कि संबद्ध आयात में आधार वर्ष और तत्काल पूर्व वर्ष, दोनों की तुलना में भारतीय उत्पादन के संबंध में भारी वृद्धि दर्शाई है।

### छ. 3.2 घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों का कीमत प्रभाव

46. घरेलू उद्योग की कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव के संबंध में यह जांच करना अपेक्षित है कि क्या भारत में समान उत्पादों की कीमत की तुलना में तथाकथित पाटित आयातों द्वारा काफी कीमत कटौती की गई है अथवा क्या इन आयातों का प्रभाव कीमतें कम करने अथवा कीमत की वृद्धि रोकने के लिए अन्यथा है जो अन्यथा सामान्य प्रक्रिया में हुई होती। संबद्ध देश से पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग की कीमतों पर प्रभाव की जांच कीमत कटौती, कम कीमत पर बिक्री, कीमत न्यूनीकरण तथा कीमत ह्रास, यदि कोई है, के संदर्भ में की गई है। इस विश्लेषण के प्रयोजन के लिए घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत, निवल बिक्री वसूली (एनएसआर) और क्षति रहित कीमत (एनआईपी) की तुलना संबद्ध देश से संबद्ध सामानों के आयातों की पहुँच कीमत से की गई है।

#### क. कीमत कटौती

47. कीमत कटौती विश्लेषण के प्रयोजन के लिए घरेलू उद्योग की निवल बिक्री कीमत की तुलना संबद्ध देश से आयातों के पहुँच मूल्य के साथ की गई है। तदनुसार, संबद्ध देश के आयातों के कटौती प्रभाव निम्नलिखित रूप में आते हैं:

क्र. सं.	विवरण	यूनिट	2016-17	2017-18	2018-19	जांच की अवधि	
						वास्तविक	वार्षिकीकृत
1	निवल बिक्री वसूली	₹/मी. टन	****	****	****	****	****
2	प्रवृत्ति	सूचकांक	100	125	121	91	91
3	पहुँच कीमत	₹/मी. टन	69,424	95,464	94,632	69,255	69,255
4	प्रवृत्ति	सूचकांक	100	138	136	100	100
5	कीमत कटौती	₹/मी. टन	****	****	****	****	****
6	प्रवृत्ति	सूचकांक	****	****	****	****	****
7	कीमत कटौती	%	****	****	****	****	****
8	कीमत कटौती	रेंज	10-20%	0-10%	0-10%	0-10%	0-10%

48. यह देखा जाता है कि संबद्ध देश से आयात घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्री कीमत से कम कीमत पर आ रहे हैं जिसके परिणामस्वरूप सकारात्मक कीमत कटौती हो रही है।

#### ख. कीमत न्यूनीकरण एवं ह्रास

49. यह निर्धारित करने के लिए कि क्या आयात घरेलू कीमतों का ह्रास कर रहे हैं अथवा क्या इन आयातों का प्रभाव कीमतों का काफी मात्रा तक न्यूनीकरण करना अथवा कीमत वृद्धि रोकना है जो अन्यथा सामान्य प्रक्रिया में

हुई होती, क्षति की अवधि में लागतों और कीमतों में परिवर्तनों की तुलना आयात कीमतों के साथ की गई थी। निम्नलिखित तालिका वास्तविक स्थिति दर्शाती है:

क्र. सं.	विवरण	यूनिट	2016-17	2017-18	2018-19	जांच की अवधि	
						वास्तविक	वार्षिकीकृत
1	बिक्री कीम लागत	₹/मी. टन	****	****	****	****	****
2	प्रवृत्ति	सूचकांक	100	109	118	113	113
3	बिक्री कीमत	₹/मी. टन	****	****	****	****	****
4	प्रवृत्ति	सूचकांक	100	125	121	91	91
5	पहुँच कीमत	₹/मी. टन	69,424	95,464	94,632	69,255	69,255
6	प्रवृत्ति	सूचकांक	100	138	136	100	100

50. यह देखा जाता है कि:

- क. संबद्ध देश से आयात पूर्व में 2018-19 तक घरेलू उद्योग की बिक्री लागत से अधिक कीमत पर थे। तथापि, आयात जांच की अवधि में घरेलू उद्योग की बिक्री लागत से कम कीमत पर थे। यह भी नोट किया जाता है कि 2017-18 से संबद्ध सामानों की बिक्री कीमतों में काफी गिरावट आई है जबकि बिक्री लागत बढ़ी।
- ख. जबकि बिक्री लागत, बिक्री कीमत और आयात कीमत में जांच की अवधि में गिरावट आई, आयातों की पहुँच कीमत में गिरावट बिक्री लागत की तुलना में बहुत अधिक और काफी थी। घरेलू उद्योग बिक्री लागत में गिरावट से कहीं अधिक कीमतें कम करने के लिए भी मजबूर था।
- ग. इस प्रकार, संबद्ध देश से संबद्ध सामानों के आयातों में कीमत वृद्धि पर रोक लगाई है जो कि अन्यथा उत्पादन लागत में वृद्धि के कारण हुई होती। घरेलू उद्योग को संबद्ध देश से संबद्ध सामानों के आयातों के कारण कीमत ह्रास हुआ है। इसके अतिरिक्त, संबद्ध आयातों ने घरेलू उद्योग की कीमतों का अत्यधिक सीमा तक ह्रास किया है।

#### ग. कम कीमत पर बिक्री

51. घरेलू उद्योग की क्षति रहित कीमत (एनआईपी) निर्धारित की गई है और कम कीमत पर बिक्री की मात्रा निकालने के लिए संबद्ध सामानों के पहुँच मूल्य से उसकी तुलना की गई है। विचाराधीन उत्पाद की एनआईपी नियमावली के अनुबंध-3 में उल्लिखित सिद्धांतों के आधार पर जांच की अवधि के लिए उत्पादन लागत से संबंधित सत्यापित सूचना/आंकड़े अपनाकर निर्धारित की गई है। विश्लेषण यह दर्शाता है कि जांच की अवधि के दौरान संबद्ध आयातों का पहुँच मूल्य घरेलू उद्योग की क्षति रहित कीमत से कम था, जैसा कि सकारात्मक कम कीमत पर बिक्री प्रभाव दर्शाने वाली निम्नलिखित तालिका से देखा जा सकता है:

क्र. सं.	विवरण	यूनिट	जांच की अवधि
1	पहुँच कीमत	₹/मी. टन	69,255
2	एनआईपी	₹/मी. टन	****
3	कम कीमत पर बिक्री	₹/मी. टन	****
4	कम कीमत पर बिक्री	%	****
5	कम कीमत पर बिक्री	रेंज	0-20

52. यह देखा जाता है कि संबद्ध देश से संबद्ध सामानों की पहुँच कीमत घरेलू उद्योग के लिए निर्धारित एनआईपी से कम थी। चीन जन. गण. के लिए कम कीमत पर बिक्री सकारात्मक और काफी है।

**छ.3.3 घरेलू उद्योग के आर्थिक मानदंड**

53. पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-II में यह प्रावधान है कि घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच में समस्त संगत आर्थिक कारकों और तत्वों जिनका घरेलू उद्योग की हालत पर प्रभाव पड़ता हो, जिसमें बिक्री, लाभ, उत्पादन, बाजार हिस्से, उत्पादकता, निवेश पर आय अथवा क्षमता उपयोग में वास्तविक और संभावित गिरावट; वे कारक जो घरेलू कीमतों, पाटन मार्जिन की मात्रा पर प्रभाव डालते हों; नकदी प्रवाह, मालसूची, रोजगार, मजदूरी, विकास, पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता पर वास्तविक और संभावित नकारात्मक प्रभाव का वस्तुपरक और निष्पक्ष मूल्यांकन शामिल होना चाहिए। घरेलू उद्योग से संबंधित विभिन्न क्षति मानदंडों पर यहां नीचे चर्चा की गई है। प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों द्वारा अपने अनुरोधों में दिए गए विभिन्न तथ्यों और तर्कों को ध्यान में रखते हुए क्षति मानदंडों की वस्तुपरक रूप से जांच की है।

**क. उत्पादन, क्षमता, क्षमता उपयोग और बिक्री**

54. क्षति की अवधि में घरेलू उद्योग की क्षमता, उत्पादन, बिक्री और क्षमता उपयोग नीचे तालिका में दिया गया है:

क्र. सं.	विवरण	यूनिट	2016-17	2017-18	2018-19	जांच की अवधि	
						वास्तविक	वार्षिकीकृत
1	क्षमता	मी. टन	****	****	****	****	****
2	प्रवृत्ति	सूचकांक	100	100	100	100	100
3	उत्पादन	मी. टन	****	****	****	****	****
4	प्रवृत्ति	सूचकांक	100	101	91	49	49
5	क्षमता उपयोग	%	****	****	****	****	****
6	प्रवृत्ति	सूचकांक	100	101	91	49	49
7	घरेलू बिक्री	मी. टन	41,604	41,339	34,813	11,952	23,904
8	प्रवृत्ति	सूचकांक	100	99	84	57	57

55. यह देखा जाता है कि:

क. घरेलू उद्योग की क्षमता क्षति की अवधि में स्थिर रही है।

ख. घरेलू उद्योग का उत्पादन एवं क्षमता उपयोग 2017-18 में आंशिक रूप से बढ़ा है, परंतु उसके बाद जांच की अवधि में उसमें काफी गिरावट आई है।

ग. घरेलू उद्योग की बिक्री में जांच की अवधि (पीओआई) में काफी गिरावट के साथ पूरी क्षति अवधि में गिरावट आई।

56. इस प्रकार, यह देखा जाता है कि घरेलू उद्योग के उत्पादन, क्षमता उपयोग और बिक्री में 2018-19 में और उसके बाद जांच की अवधि में गिरावट आई। इन मानदंडों में गिरावट काफी अधिक है और वह संबद्ध देश से आयातों में वृद्धि के परिणामस्वरूप होनी प्रतीत होती है।

**ख. बाजार हिस्सा**

57. क्षति की अवधि में घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा निम्नलिखित तालिका में दर्शाया गया है:

क्र. सं.	विवरण	यूनिट	2016-17	2017-18	2018-19	जांच की अवधि	
						वास्तविक	वार्षिकीकृत
1	घरेलू उद्योग	%	48%	39%	28%	20%	20%
2	प्रवृत्ति	सूचकांक	100	80	59	42	42
3	संबद्ध आयात	%	47%	46%	54%	79%	79%
4	प्रवृत्ति	सूचकांक	100	98	116	167	167
5	अन्य देश	%	5%	15%	17%	1%	1%
6	प्रवृत्ति	सूचकांक	100	322	363	29	29
7	कुल	%	100	100	100	100	100

58. यह देखा जाता है कि घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में क्षति की अवधि में निरंतर गिरावट आई है। घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में क्षति की अवधि में 58 आधार अंक तक गिरावट आई जब संबद्ध आयातों का हिस्सा क्षति की अवधि में 67 आधार अंकों तक बढ़ा। अन्य सभी देशों के बाजार हिस्से में भी इस अवधि में गिरावट आई।

**ग. लाभप्रदता, निवेश पर आय और नकद लाभ**

59. क्षति की अवधि में घरेलू उद्योग की लाभप्रदता, निवेश पर आय और नकद प्रवाह नीचे तालिका में दिए गये हैं:

क्र. सं.	विवरण	यूनिट	2016-17	2017-18	2018-19	जांच की अवधि	
						वास्तविक	वार्षिकीकृत
1	बिक्री की लागत	₹/मी. टन	****	****	****	****	****
2	प्रवृत्ति	सूचकांक	100	109	118	113	113
3	बिक्री कीमत	₹/मी. टन	****	****	****	****	****
4	प्रवृत्ति	सूचकांक	100	125	121	91	91
5	प्रति यूनिट लाभ	₹/मी. टन	****	****	****	****	****
6	प्रवृत्ति	सूचकांक	100	205	132	(26)	(26)
7	कुल लाभ/(हानि)	लाख ₹.	****	****	****	****	****
8	प्रवृत्ति	सूचकांक	100	203	111	(15)	(15)
9	नकद लाभ	लाख ₹.	****	****	****	****	****
10	प्रवृत्ति	सूचकांक	100	202	110	(14)	(14)
11	ब्याज पूर्व लाभ	लाख ₹.	****	****	****	****	****
12	प्रवृत्ति	सूचकांक	100	198	107	(14)	(14)
13	नियोजित पूंजी पर आय	%	****	****	****	****	****
14	प्रवृत्ति	सूचकांक	100	204	106	(18)	(18)



60. यह देखा जाता है कि:

क. घरेलू उद्योग 2018-19 तक लाभ कमा रहा था। यद्यपि, लाभ प्रति यूनिट 2017-18 में बढ़ा, तथापि 2018-19 और उसके बाद जांच की अवधि में उसमें गिरावट आई। घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में जांच की अवधि में इतनी अधिक गिरावट आई कि घरेलू उद्योग को जांच की अवधि में वित्तीय हानियां हुईं।

ख. नकद प्रवाह और निवेश पर आय ने भी लाभों की प्रवृत्ति की तरह वही प्रवृत्ति अपनाई। नकद लाभ और निवेश पर आय में 2017-18 में वृद्धि हुई और उसके बाद जांच की अवधि तक उसमें इतनी गिरावट आई कि घरेलू उद्योग को जांच की अवधि में नकद हानियां और निवेश पर नकारात्मक आय हुई।

#### घ. रोजगार, मजदूरी और उत्पादकता

61. क्षति की अवधि में घरेलू उद्योग का रोजगार, मजदूरी और उत्पादकता नीचे तालिका में दी गई है:

क्र. सं.	विवरण	यूनिट	2016-17	2017-18	2018-19	जांच की अवधि	
						वास्तविक	वार्षिकीकृत
1	कर्मचारियों की संख्या	संख्या	****	****	****	****	****
2	प्रवृत्ति	सूचकांक	100	100	104	103	103
3	वेतन एवं मजदूरी	लाख रु.	****	****	****	****	****
4	प्रवृत्ति	सूचकांक	100	102	129	52	104
5	प्रति दिन उत्पादकता	मी. टन/दिन	****	****	****	****	****
6	प्रवृत्ति	सूचकांक	100	101	91	49	49

62. यह देखा जाता है कि घरेलू उद्योग के निष्पादन में रोजगार और मजदूरी के संबंध में काफी बदलाव नहीं आया है। प्रति दिन उत्पादकता में उत्पादन में गिरावट के कारण जांच की अवधि में गिरावट आई है।

#### ङ. मालसूची

63. क्षति की अवधि में घरेलू उद्योग में मालसूची की स्थिति निम्नलिखित तालिका में दी गई है:

क्र. सं.	विवरण	यूनिट	2016-17	2017-18	2018-19	जांच की अवधि	जांच की अवधि (ए)
1	औसत मालसूची	मी. टन	****	****	****	****	****
2	प्रवृत्ति	सूचकांक	100	26	380	479	479

64. यह देखा जाता है कि घरेलू उद्योग में औसत मालसूची में क्षति अवधि की पहली दो अवधियों की तुलना में जांच की अवधि सहित में अंतिम दो अवधियों में काफी वृद्धि हुई है।

#### च. वृद्धि

65. उत्पादन, क्षमता उपयोग, घरेलू बिक्री मात्रा, मालसूची, लाभ, नकद लाभ और निवेश पर आय के संबंध में घरेलू उद्योग की वृद्धि निम्नलिखित तालिका के अनुसार है:

क्र. सं.	विवरण	यूनिट	2017-18	2018-19	जांच की अवधि वार्षिकीकृत
1	उत्पादन	वर्ष/वर्ष	1%	-10%	-46%
2	घरेलू बिक्री	वर्ष/वर्ष	-1%	-16%	-31%
3	क्षमता उपयोग	वर्ष/वर्ष	1%	-10%	-46%
4	औसत मालसूची	वर्ष/वर्ष	-74%	1362%	26%
5	घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा	वर्ष/वर्ष	-20%	-27%	-29%
6	लाभ/(हानि)	वर्ष/वर्ष	103%	-46%	-113%

क्र. सं.	विवरण	यूनिट	2017-18	2018-19	जांच की अवधि वार्षिकीकृत
7	नकद लाभ	वर्ष/वर्ष	102%	-45%	-112%
8	पीबीआईटी	वर्ष/वर्ष	98%	-46%	-113%
9	नियोजित पूंजी पर आय	वर्ष/वर्ष	104%	-48%	-117%

#### छ. पाटन मार्जिन की मात्रा

66. पाटन की मात्रा उस सीमा तक एक संकेतक है जहां तक आयात भारत में पाटित किए जा रहे हैं। जांच ने यह दर्शाया है कि जांच की अवधि में पाटन मार्जिन सकारात्मक और काफी है।

#### ज. पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता

67. घरेलू उद्योग को जांच की अवधि में वित्तीय हानियां हो रही हैं। आयातों के कारण घरेलू उद्योग के सामने आ रही प्रतिस्पर्धा से घरेलू उद्योग के प्रचालन प्रभावित हुए हैं। इसने पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता प्रभावित की है। तथापि, यह जोड़ा जा सकता है कि घरेलू उद्योग एक बहु उत्पाद कंपनी है और इसीलिए पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता अकेले विचाराधीन उत्पाद (पीयूसी) के निष्पादन के आधार पर नहीं चलती है।

#### झ. घरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाले कारक

68. आयात कीमतें बाजार में घरेलू उद्योग की कीमतों को सीधे ही प्रभावित कर रही हैं। यह नोट किया जाता है कि संबद्ध देश से संबद्ध सामानों का पहुँच मूल्य उसकी निवल बिक्री कीमत से ही कम नहीं है बल्कि घरेलू उद्योग की क्षति रहित कीमत से भी कम है। इसके अतिरिक्त, संबद्ध आयातों की पहुँच कीमतों ने घरेलू उद्योग की का ह्रास किया है जिससे वित्तीय हानियां हुई हैं। तीसरे देशों से संबद्ध सामानों के आयात मात्रा में नगण्य हैं और घरेलू उद्योग को क्षति नहीं पहुँचा रहे हैं। विचाराधीन उत्पाद के लिए मांग देश में क्षमताओं से कहीं अधिक है और वह घरेलू उद्योग को क्षति का कारण नहीं हो सकती। पाटित आयात बाजार में उत्पाद की कीमतों को प्रभावित कर रहे हैं। इस प्रकार, अनंतिम रूप से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि घरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक संबद्ध देश से संबद्ध सामानों के पाटित आयात हैं।

69. प्राधिकारी ने क्षति तथा कारणात्मक संपर्क के संबंध में घरेलू उद्योग और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए विभिन्न अनुरोधों को ध्यान में रखा है और रिकार्ड में उपलब्ध तथ्यों तथा लागू कानूनों पर विचार करते हुए उसका विश्लेषण किया है। पूर्ववर्ती पैराओं में प्राधिकारी द्वारा किया गया क्षति विश्लेषण यथा तथ्यतः घरेलू उद्योग तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों को हल करता है।

70. यह देखा जाता है कि उत्पादन, क्षमता उपयोग, घरेलू बिक्री मात्रा, मालसूची, लाभ, नकद लाभ और निवेश पर आय के संदर्भ में घरेलू उद्योग की वृद्धि जांच की अवधि में प्रतिकूल और नकारात्मक थी।

71. जहां तक इस तर्क का संबंध है कि कीमत कटौती और लाभ के बीच कोई सह संबंध नहीं है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि सकारात्मक कीमत कटौती का अर्थ हमेशा यह नहीं होता कि घरेलू उद्योग के निष्पादन में हमेशा गिरावट होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त, उच्च कीमत कटौती का अभिप्राय यह है कि घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत आयात कीमत से अधिक थी। यह नोट किया जाता है कि जांच की अवधि के दौरान आयात कीमत में भारी गिरावट के कारण घरेलू उद्योग अपनी बिक्री कीमतें काफी कम करने के लिए मजबूर हुआ है। इसके अतिरिक्त, कम हो रहीं कीमतों के बावजूद घरेलू उद्योग ने काफी बिक्री मात्रा खोई है। कीमत कटौती तथा परिणामस्वरूप आयात मात्रा में वृद्धि के कारण बिक्री कीमत में कमी के बावजूद बिक्री मात्रा में गिरावट यह दर्शाती है कि घरेलू उद्योग ने अपनी कीमतें कम कीं और मात्राएं भी खोईं जबकि संबद्ध आयात घरेलू उद्योग की कीमतों की कटौती कर रहे थे और उनकी आयात मात्राएं भी बढ़ीं।

72. जहां तक इस तर्क का संबंध है कि चीनी आयात किफायतों के कारण प्रतिस्पर्धी कीमतों पर चल रही हैं, प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटन मार्जिन आवेदक द्वारा प्रस्तावित सामान्य मूल्य और अनंतिम जांच परिणाम के प्रयोजन के लिए प्राधिकारी द्वारा निर्धारित निर्मित सामान्य मूल्य (सीएनवी) पर विचार करते हुए सकारात्मक है। यह तथ्य दर्शाता है कि इस देश में संबद्ध आयात पाटित कीमतों पर आए हैं।

73. जहां तक जांच की अवधि के कम से कम दो माह में नकारात्मक कीमत कटौती का संबंध है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि कीमत कटौती जांच की अवधि के लिए निर्धारित की जानी अपेक्षित है। यह पूरी तरह संभव है कि आयात लेन-देनों अथवा महीनों में कीमत कटौती सकारात्मक और कुछ अन्य आयात लेन-देनों या महीनों में नकारात्मक हो। तथापि, प्राधिकारी के लिए पूरी क्षति अवधि के लिए भारित औसत कीमत कटौती निर्धारित करना अपेक्षित है।

74. जहां तक घरेलू उद्योग की कम उत्पादन क्षमता के संबंध में तर्कों का संबंध है, यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग के क्षमता उपयोग में क्षति की अवधि में लगभग 50 प्रतिशत की गिरावट आई जो काफी अधिक है।

75. जहां तक कच्चे माल आदि पर आधारित इनपुट लागत में उतार-चढ़ाव का संबंध है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि यह दर्शाने के लिए कोई सत्यापनीय सूचना नहीं दी गई है कि इन कारकों ने निर्यात कीमत प्रभावित की और सामान्य मूल्य प्रभावित नहीं किया।

76. जहां तक तथाकथित संयंत्र बंदी का संबंध है, यह देखा जाता है कि घरेलू उद्योग के उत्पादन और क्षमता उपयोग में लगभग 50 प्रतिशत तक गिरावट आई। इसके अतिरिक्त, प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग में मालसूची की प्रवृत्ति की जांच की। यह देखा जाता है कि घरेलू उद्योग में अनिवार्य रूप से पूरी अवधि में मालसूची थी जो स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि बिक्री में गिरावट उत्पादन के संभावित अभाव के कारण नहीं है।

77. जहां तक इस तर्क का संबंध है कि ह्रास केवल जांच की अवधि में है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग के निष्पादन में उत्पादन, क्षमता उपयोग, घरेलू बिक्री, बाजार हिस्सा, लाभ प्रति यूनिट, कुल लाभ, नकद लाभ, मालसूची के संबंध में 2018-19 में भी ह्रास हुआ। यह ह्रास जो 2018-19 में शुरू हुआ, आगे जारी रहा और जांच की अवधि में और अधिक हो गया।

#### ज. क्षति मार्जिन

78. प्राधिकारी ने नियमावली के अनुबंध-III के साथ पठित नियमावली में उल्लिखित सिद्धांतों के आधार पर घरेलू उद्योग के लिए क्षति रहित कीमत (एनआईपी) निर्धारित की है। घरेलू समान उत्पाद की एनआईपी जांच की अवधि के लिए निर्माण लागत तथा बिक्री लागत से संबंधित सत्यापित सूचना/आंकड़ों को अपनाकर निर्धारित की गई है। घरेलू उद्योग की एनआईपी नियमावली के अनुबंध-3 के अनुसार निकाली गई है। एनआईपी निर्धारित करने के लिए क्षति की अवधि में घरेलू उद्योग द्वारा कच्ची सामग्री के सर्वोत्तम उपयोग को माना गया है। यही व्यवहार यूटिलिटीयों के साथ किया गया। क्षति की अवधि में उत्पादन क्षमता के सर्वोत्तम उपयोग पर विचार किया गया है। एनआईपी के प्रयोजन के लिए जांच की अवधि में उत्पादन सर्वोत्तम क्षमता उपयोग पर विचार करके परिकलित किया गया है और वही उत्पादन प्रति यूनिट निर्धारित लागत निकालने के लिए माना गया है। यह सुनिश्चित किया जाता है कि कोई असाधारण अथवा अनावर्ती व्यय उत्पादन लागत में न लगाए जाएं। विचाराधीन उत्पाद के लिए नियोजित औसत पूंजी (अर्थात् औसत निवल अचल परिसंपत्तियां एवं औसत कार्यशील पूंजी) पर उपयुक्त आय (कर पूर्व 22 प्रतिशत की दर से) अनुबंध-3 में निर्धारित किए गए अनुसार क्षति रहित कीमत निकालने के लिए ब्याज, कारपोरेट कर तथा लाभ की वसूली के लिए अनुमति दी गई थी और प्राधिकारी द्वारा पाटनरोधी जांचों में निरंतर अपनाई जा रही है।

79. संबद्ध देशों से सभी असहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए प्राधिकारी ने उपलब्ध तथ्यों के आधार पर पहुँच कीमत निर्धारित की है।

80. उपर्युक्त निर्धारित पहुँच कीमत और क्षति रहित कीमत के आधार पर उत्पादकों/निर्यातकों के लिए क्षति मार्जिन प्राधिकारी द्वारा निर्धारित किया गया है और वह निम्नलिखित तालिका में दिया गया है:

देश	उत्पादक का नाम	क्षति रहित कीमत (अमेरिकी डॉलर/मी. टन)	पहुँच मूल्य (अमेरिकी डॉलर/मी. टन)	क्षति मार्जिन अमेरिकी डॉलर/मी. टन	क्षति मार्जिन (%)	क्षति मार्जिन % (रेंज)
चीन जन. गण.	वनहुआ केमिकल ग्रुप कं. लिमिटेड	****	****	****	****	0-20
	अन्य	****	****	****	****	0-20

**ज. क्षति संबंधी निष्कर्ष**

81. संबद्ध उत्पाद के आयातों और घरेलू उद्योग के निष्पादन की जांच यह दर्शाती है कि आयातों की मात्रा पूर्ण दृष्टि से तथा भारत में उत्पादन तथा मांग के संबंध में बढ़ी है। आयात घरेलू उद्योग की कीमतों की कटौती कर रहे हैं और कम कीमत पर बिक्री भी सकारात्मक है। संबद्ध देश से संबद्ध सामानों के आयातों ने कीमत वृद्धि रोकी है जो अन्यथा उत्पादन लागत में वृद्धि के कारण हुई होती। घरेलू उद्योग को संबद्ध देश से संबद्ध सामानों के आयातों के कारण कीमत ह्रास हुआ है। इसके अतिरिक्त, संबद्ध आयातों ने घरेलू उद्योग की कीमतों को बहुत अधिक मात्रा तक न्यूनीकृत किया है।

82. यह भी नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग के उत्पादन, क्षमता उपयोग और घरेलू बिक्री में जांच की अवधि में काफी गिरावट के साथ क्षति की अवधि में गिरावट आई। घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में जांच की अवधि में काफी गिरावट से क्षति की अवधि में गिरावट आई है। साथ ही, संबद्ध देश से संबद्ध आयातों के बाजार हिस्से में काफी वृद्धि हुई है। यह भी नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग में काफी मालसूची है।

83. घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में क्षति की अवधि में काफी गिरावट आई और घरेलू उद्योग को जांच की अवधि में वित्तीय हानियां हुईं। घरेलू उद्योग का निष्पादन नकद प्रवाह, पीबीआईटी और निवेश पर आय के संबंध में कम हुआ। घरेलू उद्योग को जांच की अवधि में नकद हानियां और निवेश पर नकारात्मक आय हुई। इसके अतिरिक्त, घरेलू उद्योग की वृद्धि कई क्षति मानदंडों के संबंध में जांच की अवधि में नकारात्मक हुई।

84. उपर्युक्त को देखते हुए, प्राधिकारी अनंतिम रूप से यह निष्कर्ष निकालते हैं कि घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है।

**झ. गैर-आरोपण विमोक्षण**

85. नियमावली के अनुसार, प्राधिकारी के लिए अन्य बातों के साथ-साथ पाटित आयातों को छोड़कर किसी अन्य ज्ञात कारकों की जांच करना अपेक्षित है जो साथ-साथ घरेलू उद्योग को क्षति पहुँचा रहे हैं ताकि इन अन्य कारकों के कारण क्षति पाटित आयातों के कारण न हो। इस संबंध में, जो कारक संगत हो सकते हैं, उनमें अन्य बातों के साथ-साथ पाटित कीमतों पर न बेचे गए आयातों की मात्रा तथा कीमतें, मांग में संकुचन अथवा खपत के पैटर्न में परिवर्तन, व्यापार प्रतिबंधात्मक परिपाटियां और विदेशी तथा घरेलू उत्पादकों के बीच प्रतिस्पर्धा, प्रौद्योगिकी में विकास तथा निर्यात निष्पादन और घरेलू उद्योग की उत्पादकता शामिल हैं। नीचे यह जांच की गई है कि क्या पाटित आयातों को छोड़कर किन्हीं अन्य कारकों से घरेलू उद्योग को क्षति हुई है।

86. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने अनुरोध किया है कि आवेदक को हुई क्षति अन्य कारणों से है न कि संबद्ध देश से आयातों के कारण। प्राधिकारी नोट करते हैं कि हितबद्ध पक्षकारों ने यह सिद्ध करते हुए कोई सत्यापनीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है कि घरेलू उद्योग को पाटित आयातों को छोड़कर अन्य कारकों के कारण क्षति हुई है। यहां तक कि यद्यपि विरोधी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए दावे केवल अवधारणाएं हैं तो उनकी रिकार्ड में उपलब्ध सूचना के आधार पर जांच की गई है।

**क. तीसरे देशों से आयातों की मात्रा और कीमतें**

87. संबद्ध देश से आयातों का, आयातों में लगभग 98 प्रतिशत हिस्सा है। इस प्रकार, यह नहीं कहा जा सकता कि दूसरे देशों से आयात क्षति पहुँचा रहे हैं।

**ख. उत्पाद के लिए मांग**

88. संबद्ध सामानों के लिए मांग पूर्व वर्ष से तुलना करने पर जांच की अवधि में आंशिक गिरावट के साथ क्षति की अवधि में बढ़ी है। तथापि, जांच की अवधि में मांग आधार वर्ष में मांग से काफी अधिक थी। मांग में गिरावट घरेलू उद्योग को हुई क्षति का कारण नहीं हो सकती।

**ग. निर्यात निष्पादन**

89. ऊपर जांच की गई क्षति संबंधी सूचना घरेलू उद्योग की उसके घरेलू बाजार के संदर्भ में निष्पादन से ही संबंधित है। इस प्रकार, हुई क्षति घरेलू उद्योग के निर्यात निष्पादन के कारण नहीं हो सकती।

**घ. प्रौद्योगिकी में विकास**

90. प्रौद्योगिकी में काफी परिवर्तनों की मौजूदगी, जिससे घरेलू उद्योग को क्षति हो सकती है, के संबंध में किसी भी हितबद्ध पक्षकार द्वारा कोई साक्ष्य नहीं दिया गया है।

**ङ. घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित और बेचे जा रहे अन्य उत्पादों का निष्पादन**

91. प्राधिकारी ने केवल संबद्ध सामानों के निष्पादन से संबंधित आंकड़ों पर ही विचार किया है। अतः उत्पादित किए गए और बेचे गए अन्य उत्पादों का निष्पादन घरेलू उद्योग को क्षति का संभावित कारण नहीं है।

**च. खपत के पैटर्न में परिवर्तन**

92. विचाराधीन उत्पाद के खपत पैटर्न में कोई वास्तविक परिवर्तन नहीं हुआ है। अतः खपत के पैटर्न में परिवर्तनों से घरेलू उद्योग को क्षति नहीं हुई है।

**छ. व्यापार प्रतिबंधात्मक परिपाटियां**

93. संबद्ध सामानों का आयात किसी भी तरीके से प्रतिबंधित नहीं है और उनका देश में स्वतंत्र रूप से आयात किया जा सकता है। यह बताने के लिए किसी भी हितबद्ध पक्षकार द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है कि विदेशी और घरेलू उत्पादकों के बीच प्रतिस्पर्धा की शर्तों में कोई परिवर्तन हुआ है।

**ज. कारणात्मक संपर्क संबंधी निष्कर्ष**

94. इस प्रकार, यह नोट किया जाता है कि नियमावली के तहत सूचीबद्ध अन्य ज्ञात कारक यह नहीं दर्शाते कि घरेलू उद्योग को इन अन्य कारकों के कारण क्षति हो सकती है। प्राधिकारी ने यह भी जांच की है कि क्या उत्पाद के पाटन से घरेलू उद्योग को क्षति हुई है। निम्नलिखित मानदंड यह दर्शाते हैं कि घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति पाटित आयातों के कारण हुई है:

- क. संबद्ध देश से संबद्ध सामानों के आयातों में पूर्ण दृष्टि से तथा उत्पादन एवं खपत के संबंध में वृद्धि हुई है।
- ख. संबद्ध आयातों के बाजार हिस्से में वृद्धि हुई है जबकि घरेलू उद्योग के हिस्से में उसी अवधि में गिरावट आई है। यद्यपि मांग भी कम हुई है, तथापि घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में गिरावट मांग में गिरावट से अधिक है।
- ग. भारत में आने वाले कम कीमत के पाटित आयातों के कारण कीमत ह्रास है।
- घ. पाटित आयात घरेलू उद्योग की कीमतों की कटौती कर रहे हैं। कम कीमत पर बिक्री काफी और सकारात्मक है।
- ङ. परिणामस्वरूप, घरेलू उद्योग के उत्पादन और बिक्री में इस अवधि में गिरावट आई है।
- च. घरेलू उद्योग के लाभ, नकद लाभ और घरेलू उद्योग की नियोजित पूंजी पर आय जांच की अवधि में नकारात्मक हुए हैं।

**ट. भारतीय उद्योग का हित एवं अन्य मुद्दे**

95. प्राधिकारी मानते हैं कि पाटनरोधी शुल्क लगाने से भारत में उत्पाद के कीमत स्तर प्रभावित हो सकते हैं। तथापि, भारतीय बाजार में उचित प्रतिस्पर्द्धा पाटनरोधी उपाय लगाए जाने से कम नहीं होगी। इसके विपरीत, पाटनरोधी उपाय लगाए जाने से पाटन की परिपाटियों द्वारा प्राप्त अनुचित लाभ समाप्त होंगे, घरेलू उद्योग की गिरावट रुकेगी और संबद्ध सामानों के ग्राहकों को व्यापक विकल्प की उपलब्धता बनाए रखने में मदद मिलेगी। पाटनरोधी शुल्कों का प्रयोजन सामान्य रूप में पाटन की अनुचित व्यापारिक परिपाटियों द्वारा घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति समाप्त करना है ताकि भारतीय बाजार में खुली और उचित प्रतिस्पर्द्धा की स्थिति पुनः स्थापित की जा सके जो कि देश के सामान्य हित में है। अतः पाटनरोधी शुल्क लगाने से ग्राहकों को उत्पाद की उपलब्धता प्रभावित नहीं होगी। प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटनरोधी उपाय लगाने से किसी भी दशा में संबद्ध देशों से आयात प्रतिबंधित नहीं होंगे और इसीलिए ग्राहकों को उत्पाद की उपलब्धता प्रभावित नहीं होगी।

**ठ. निष्कर्ष एवं सिफारिशें**

96. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों और उनमें उठाए गए मुद्दों की जांच करने और रिकार्ड में तथ्यों पर विचार करने के बाद, यह नोट किया जाता है कि:

क. जो विचाराधीन उत्पाद पाटित कीमतों पर संबद्ध देश से भारत को निर्यात किए गए हैं।

ख. घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है।

ग. घरेलू उद्योग को क्षति संबद्ध देश से पाटित आयातों के कारण हुई है।

97. प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच की शुरुआत की गई थी और सभी हितबद्ध पक्षकारों को अधिसूचित की गई थी तथा घरेलू उद्योग, निर्यातकों, आयातकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को पाटन, क्षति एवं कारणात्मक संपर्क के पहलू पर सकारात्मक सूचना प्रदान करने के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान किया गया था। नियमावली में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार, पाटन, क्षति एवं कारणात्मक संपर्क के बारे में जांच शुरू करने और जांच करने पर प्राधिकारी का यह मत है कि पाटन और क्षति को दूर करने के लिए जांच पूरी होने तक अनंतिम शुल्क लगाए जाने की आवश्यकता है। अतः प्राधिकारी संबद्ध देश से संबद्ध सामानों के आयातों पर अनंतिम पाटनरोधी शुल्क लगाया जाना आवश्यक समझते हैं और उसकी सिफारिश करते हैं।

98. नियमावली के नियम 4(घ) के साथ पठित नियम 17(1)(ख) में निहित प्रावधान के अनुसार, प्राधिकारी घरेलू उद्योग को क्षति समाप्त करने के लिए पाटन मार्जिन एवं क्षति मार्जिन से कमतर के बराबर पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने की सिफारिश करते हैं। तदनुसार, केंद्र सरकार द्वारा जारी की जाने वाली अधिसूचना की तारीख से संबद्ध देश के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध सामानों के सभी आयातों पर नीचे दी गई शुल्क तालिका के कॉलम 7 में उल्लिखित राशि के बराबर निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाये जाने की सिफारिश करते हैं।

**शुल्क तालिका**

क्रम सं.	शीर्ष/उप-शीर्ष	सामानों का विवरण	मूल देश	निर्यात का देश	उत्पादक	शुल्क	यूनिट	मुद्रा
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	29214110	एनिलिन अथवा एनिलिन तेल	चीन जन. गण.	चीन जन. गण. सहित कोई देश	वनहुआ केमिकल ग्रुप कं. लिमिटेड	65.91	मी. टन	अमेरिकी डॉलर
2	29214110	एनिलिन अथवा एनिलिन तेल	चीन जन. गण.	चीन जन. गण. सहित कोई देश	क्रम संख्या 1 में उल्लिखित के अलावा कोई उत्पादक	150.80	मी. टन	अमेरिकी डॉलर
3	29214110	एनिलिन अथवा एनिलिन तेल	चीन जन. गण. के अलावा कोई देश	चीन जन. गण.	कोई अन्य	150.80	मी. टन	अमेरिकी डॉलर

**ड. आगे की प्रक्रिया**

99. प्राथमिक जांच परिणाम अधिसूचित करने के बाद निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जाएगी:

- प्राधिकारी सभी हितबद्ध पक्षकारों से इन अनंतिम जांच परिणामों पर टिप्पणियां आमंत्रित करते हैं और यदि वे प्राधिकारी द्वारा संगत मानी जाती हैं तो अंतिम जांच परिणाम में उन पर विचार किया जाएगा।



- ii. घरेलू उद्योग, निर्यातक, आयातक और अन्य हितबद्ध पक्षकार जो संबंधित जाने जाएं, को प्राधिकारी द्वारा अलग से पत्र भेजा जा रहा है जो इन प्राथमिक जांच परिणामों के प्रकाशन की तारीख से 30 दिनों के भीतर अपने ज्ञात विचार दे सकते हैं।
- iii. अन्य कोई हितबद्ध पक्षकार भी इन जांच परिणामों के प्रकाशन की तारीख से 30 दिनों के भीतर अपने ज्ञात विचार दे सकते हैं।
- iv. प्राधिकारी सभी हितबद्ध पक्षकारों को इस जांच से संगत अपने विचार देने के लिए अवसर प्रदान करने हेतु नियम 6(6) के अनुसार मौखिक सुनवाई आयोजित करेंगे और मौखिक सुनवाई के दौरान उठाए गए मुद्दों और चिंताओं की अंतिम जांच परिणामों में जांच की जाएगी।
- v. मौखिक सुनवाई की तारीख डीजीटीआर की वेबसाइट (dgtr.gov.in) पर घोषित की जाएगी।
- vi. प्राधिकारी आवश्यक समझी जाने वाली सीमा तक आगे सत्यापन करेंगे।
- vii. प्राधिकारी अंतिम जांच परिणाम जारी करने से पूर्व नियमावली के अनुसार अनिवार्य तथ्य प्रकट करेंगे।

भूपिन्दर एस. भल्ला, अपर सचिव एवं निर्दिष्ट प्राधिकारी

**MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**  
(Department of Commerce)  
(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 12th June, 2020

**Case No. ADD(OI) 33/2019**

**PRELIMINARY FINDINGS**

**Subject : Anti-dumping investigation concerning the imports of Aniline from China PR**

**F. No. 6/42/2019-DGTR.—A. BACKGROUND OF THE CASE**

1. M/s Gujarat Narmada Valley Fertilizers & Chemicals Limited (hereinafter also referred to as the “Applicant”) filed an application, before the Designated Authority in accordance with the Customs Tariff Act 1975 as amended from time to time (hereinafter also referred as the Act) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Antidumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 (hereinafter also referred as the “Anti-Dumping Rules” or “Rules”) for initiation of anti-dumping investigation concerning imports of Aniline (hereinafter also referred to as the “product under consideration” or “PUC” or “subject goods”) from China PR (hereinafter also referred to as the subject country).
2. The Authority, on the basis of a prima facie evidence submitted by the Applicant, issued a public notice vide Notification No. 33/2019–DGTR dated 24<sup>th</sup> January, 2020, published in the Gazette of India, initiating the subject investigation in accordance with Section 9A of the Act, read with Rule 5 of the Rules, to determine the existence, degree and effect of any alleged dumping of the subject goods originating in or exported from subject country and to recommend the amount of anti-dumping duty, which if levied, would be adequate to remove the alleged injury to the domestic industry.

**B. PROCEDURE**

3. The procedure described herein below has been followed with regard to the subject investigation: -
  - a. The Authority notified the Embassy of the subject country in India about the receipt of the present anti-dumping application before proceeding to initiate the investigation in accordance with sub-rule (5) of Rule 5 supra.

- b. The Authority issued a public notice dated 24<sup>th</sup> January 2020 published in the Gazette of India Extraordinary, initiating anti-dumping investigation concerning the import of subject goods from the subject country.
- c. The Embassy of subject country in India was informed about the initiation of the investigation in accordance with Rule 6(2) of the Rules. The Authority sent a copy of the initiation notification to the Government of the Subject Country, through its Embassy in India, known producers/exporters from the subject country, known importers/users and the domestic industry as well as other domestic producers as per the addresses made available by the Applicant and requested them to make their views known in writing within the prescribed time limit.
- d. The Authority provided a copy of the non-confidential version of the application to the known producers/exporters and to the Government of the subject country, through its Embassy in India in accordance with Rule 6(3) of the Rules supra. A copy of the non-confidential version of the application was also made available in the public file and provided to other interested parties, wherever requested.
- e. The Authority also forwarded copy of the notice to known producers/ exporters from the subject country, known importers/users in India, other Indian producers and the domestic industry as per the addresses made available by the Applicant and requested them to make their views known in writing within time limit given in the initiation notification.
- f. The Embassy of the subject country in India was also requested to advise the exporters/producers from its country to respond to the questionnaire within the prescribed time limit. A copy of the letter and questionnaire sent to the producers/exporters was also sent to the Embassy along with the names and addresses of the known producers/exporters from the subject country.
- g. The Authority sent exporter's questionnaire to the following known producers/exporters in the subject country in accordance with Rule 6(4) of the Rules: -
  - i. M/s Sinopec Nanjing Chemical Industries Co., Limited
  - ii. M/s Bayer Material Science (Shanghai) Co., Limited
  - iii. M/s Jilin Connell Chemical Industry Co., Limited
  - iv. M/s Shanxi Tianji Coal Chemical Group Co., Limited
  - v. M/s Shandong Jinling Chemical Co., Limited
  - vi. M/s Jiangsu Ruxiang Chemical Co., Limited
  - vii. M/s Henan Kaipu Chemical Co., Limited
  - viii. M/s BASF (China) Co., Limited
  - ix. M/s Yantai Wanhua Polyurethanes Co., Limited
  - x. M/s Hebei Jiheng Chemical Group Co., Limited
  - xi. M/s Shandong Haihua Co., Limited
- h. In response to the above notification, following producers, their related exporters/traders have submitted the exporter questionnaire responses: -
  - i. M/s Wanhua Chemical Group Co., Limited
  - ii. M/s Wanhua Chemical (Hong Kong) Co., Limited
  - iii. M/s Kempar Energy Pte. Limited.
  - iv. M/s Wanhua Chemical (Yantai) Trading Co., Limited
  - v. M/s Wanhua Chemical (Ningbo) Co., Limited
  - vi. M/s Wanhua Chemical (Ningbo) Trading Co., Limited

- i. The Authority sent questionnaires to the following known importers / users of subject goods in India calling for necessary information in accordance with Rule 6(4) of the Rules: -
  - i. M/s NOCIL Limited
  - ii. M/s Aarti Industries Limited
  - iii. M/s Bodal Chemicals Limited
  - iv. M/s Bhageria Industries Limited
  - v. M/s Kutch Chemicals Industries Limited
  - vi. M/s Mayur Dyechem Intermediate LLP
  - vii. M/s Industrial Solvents & Chemicals Private Limited
- j. In response to the above notification, following importers/users have submitted importer questionnaire responses:
  - i. M/s Bhageria Industries Limited
  - ii. M/s Bodal Chemicals Limited
  - iii. M/s Kutch Chemicals Industries Limited
  - iv. M/s Colourtex Industries Private Limited
  - v. M/s Mayur Dye Chem Intermediates LLP
- k. Further, the following interested parties have filed legal submissions over the investigation: -
  - i. M/s Jemby Chem Limited
  - ii. M/s Bharat Organics Limited
  - iii. M/s Nutan Dye Chem Private Limited
  - iv. M/s Remik Chemicals Private Limited
  - v. M/s Laxmi Organic Industries Limited
  - vi. The Dyestuffs Manufacturers' Association of India (DMAI)
  - vii. M/s Wanhua Chemical Group Co., Limited, M/s Wanhua Chemical (Hong Kong) Co., Limited, M/s Wanhua Chemical (Yantai) Trading Co., Limited, M/s Wanhua Chemical (Ningbo) Co., Limited., and M/s Wanhua Chemical (Ningbo) Trading Co., Limited collectively.
- l. The Authority made available non-confidential version of the evidence presented by various interested parties in the form of e-file through email for the interested parties.
- m. Request was made to the Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics (DGCI&S) to provide transaction-wise details of imports of subject goods for the past three years, and the period of investigation, which has been received by the Authority. The Authority has relied upon DGCI&S data for computation of the volume and values of imports and its analysis after due examination of the transactions.
- n. The Non-injurious Price (NIP) based on the optimum cost of production and cost to make & sell the subject goods in India based on the information furnished by the domestic industry on the basis of Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) and Annexure III to the Rules has been worked out so as to ascertain whether Anti-Dumping duty lower than the dumping margin would be sufficient to remove injury to the Domestic Industry.
- o. The information/ data submitted by the Applicant has been verified to the extent deemed necessary and relied upon for the purpose of preliminary findings.

- p. The period of investigation for the purpose of present investigation is 1<sup>st</sup> April 2019 to 30<sup>th</sup> September 2019 (6 months). The injury examination period has, however, been considered as the period from 2016-17, 2017-18, 2018-19 and the period of investigation.
- q. Information provided by the interested parties on confidential basis was examined with regard to sufficiency of the confidentiality claim. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims wherever warranted and such information has been considered as confidential and not disclosed to other interested parties. Wherever possible, parties providing information on confidential basis were directed to provide sufficient non-confidential version of the information filed on confidential basis.
- r. Wherever an interested party has refused access to, or has otherwise not provided necessary information during the course of the present investigation, or has significantly impeded the investigation, the Authority has considered such parties as non-cooperative and recorded the present preliminary findings on the basis of the facts available.
- s. The Authority has considered all the arguments raised and information provided by all the interested parties at this stage, to the extent the same are supported with evidence and considered relevant to the present investigation. The Authority will further examine the evidentiary documents submitted by the interested parties subsequent to preliminary findings, which will form the basis for conclusions at the time of final findings.
- t. ‘\*\*\*\*’ in this notification represents information furnished by an interested party on confidential basis and so considered by the Authority under the Rules.
- u. The exchange rate adopted by the Authority for the subject investigation is 1 US \$= Rs. 70.73.

## C. PRODUCT UNDER CONSIDERATION AND LIKE ARTICLE

4. At the stage of initiation, the product under consideration was defined as: -

*“The product under consideration for the purpose of present investigation is “Aniline” which is also known as “Aniline Oil”. Aniline is a transparent, oily liquid and is a primary amine compound. Its colour transforms to light pale-yellow liquid when freshly distilled. Its colour darkens when exposed to light or air. Aniline is a basic organic chemical, essential for vital industries such as drugs, pharmaceuticals, dyes and dye intermediates.*

*The subject products are classified under Chapter Heading 29 under the code 29214110. The customs classification is indicative only and in no way, binding upon the product scope.”*

### C.1. Submissions made by the domestic industry

5. Following submissions have been made by the domestic industry with regard to the product under consideration:
- a. The product under consideration is Aniline, also known as Aniline Oil, which is a transparent oily liquid and is used in drugs, pharmaceuticals, dyes and dye intermediates.
  - b. The product is classified under custom heading 2921 41 10 of the Customs Tariff Act, 1975.
  - c. The goods produced by the Applicant are like article to the imported goods as they are comparable in terms of physical and chemical characteristics, manufacturing process & technology, functions & uses, product specifications, pricing, distribution & marketing and tariff classification of the goods, and are technically and commercially substitutable. There is no known significant difference in the technology employed by the domestic industry and the producers in subject country

### C.2. Submissions made by other interested parties

6. No submissions have been made by any other interested party with regard to the scope of product under consideration.

**C.3. Examination by the Authority**

7. The submissions made by the domestic industry with regard to product under consideration related issues are examined and addressed hereunder.
8. The product under consideration in the present investigation is Aniline which is a basic organic chemical for drugs, pharmaceuticals, dyes and dye intermediates. The product is also called Aniline oil.
9. The Authority has considered the PUC as under:-

*The product under consideration for the purpose of present investigation is “Aniline” which is also known as “Aniline Oil”. Aniline is a transparent, oily liquid and is a primary amine compound. Its colour transforms to light pale-yellow liquid when freshly distilled. Its colour darkens when exposed to light or air. Aniline is a basic organic chemical, essential for vital industries such as drugs, pharmaceuticals, dyes and dye intermediates.*

*The subject products are classified under Chapter Heading 29 under the code 29214110. The customs classification is indicative only and in no way, binding upon the product scope.*

10. It has been noted from the information available on record that the product produced by the Domestic Industry is like article to product under consideration imported from subject countries. The product produced by the Domestic Industry, and subject goods imported from subject countries are comparable in terms of physical & chemical characteristics, manufacturing process & technology, functions and uses, product specifications, pricing, distribution & marketing and tariff classification of the goods. The two are technically and commercially substitutable. The consumers have used and are using the two interchangeably. The contention of the Applicant has not been disputed by the other interested parties. The Authority provisionally holds that the subject goods produced by the domestic industry are like article to the product imported from subject countries in terms of Rule 2(d) of the AD Rules.
11. The product under consideration is classified under the Chapter Heading 29 under the tariff code 2921 41 10. The customs classification is only indicative and is not binding on the scope of the product under consideration.

**D. SCOPE OF DOMESTIC INDUSTRY & STANDING****D.1. Submissions made by the domestic industry**

12. The domestic industry has made the following submissions with regard to the scope of domestic industry and standing:
  - a. The Applicant is the sole producer of the subject goods in India.
  - b. The Applicant has not imported the subject goods from subject country and is not related to any exporter in the subject country or importer of subject goods in India.
  - c. The Applicant satisfies the requirement of Rule 2(b) and Rule 5(3) of the Rules.

**D.2. Submissions made by other interested parties**

13. No submissions have been made by other interested parties with regard to the scope and standing of domestic industry.

**D.3. Examination by the Authority**

14. Rule 2(b) of the Rules defines domestic industry as under:

*“(b) “domestic industry” means the domestic producers as a whole engaged in the manufacture of the like article and any activity connected therewith or those whose collective output of the said article constitutes a major proportion of the total domestic production of that article except when such producers are related to the exporters or importers of the alleged dumped article or are themselves importers thereof in such case the term ‘domestic industry’ may be construed as referring to the rest of the producers”.*



15. The Application has been filed by M/s Gujarat Narmada Valley Fertilizers & Chemicals Limited. There is no other producer of the subject goods in India. The Applicant has not imported the subject goods from subject country and is not related to any exporter in the subject country or importer in India.
16. Accordingly, the Authority holds that the Applicant constitutes domestic industry within the meaning of Rule 2(b) of the Rules and considers that the application satisfies the criteria of standing in terms of Rule 5(3) of the Rules.

### **Confidentiality**

#### **Submissions made by domestic Industry**

17. No submissions have been made by domestic industry with regard to confidentiality.

#### **Submissions made by other interested parties**

18. Excessive confidentiality has been claimed by the petitioner as it has not provided any information at all in the Section VI of the petition. Since it is a multi-product company, the annual report does not provide information in relation to product under consideration. Though, the capacity and capacity utilization of the subject goods are disclosed in the annual report, the same has also been claimed confidential.

### **Examination by the Authority**

19. Various submissions made by the Applicant as well as other interested parties during the course of the investigation with regard to confidentiality, to the extent considered relevant by the Authority, have been examined and addressed as follows.
20. The Authority made available non-confidential version of the information provided by various interested parties to all interested parties through the public file containing non-confidential version of evidences submitted by various interested parties for inspection as per Rule 6(7).

- (i) With regard to confidentiality of information, Rule 7 of the Rules provides as follows:

*“Confidential information: (1) Notwithstanding anything contained in sub-rules (2), (3) and (7) of rule 6, sub-rule(2) of rule 12, sub-rule(4) of rule 15 and sub-rule (4) of rule 17, the copies of applications received under sub-rule (1) of rule 5, or any other information provided to the designated authority on a confidential basis by any party in the course of investigation, shall, upon the designated authority being satisfied as to its confidentiality, be treated as such by it and no such information shall be disclosed to any other party without specific authorization of the party providing such information.*

*(2) The designated authority may require the parties providing information on confidential basis to furnish non-confidential summary thereof and if, in the opinion of a party providing such information, such information is not susceptible of summary, such party may submit to the designated authority a statement of reasons why summarization is not possible.*

*(3) Notwithstanding anything contained in sub-rule (2), if the designated authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorise its disclosure in a generalized or summary form, it may disregard such information.”*

- (ii) As regards the contentions with regard to confidentiality of information, it is noted that information provided by the interested parties on confidential basis was examined with regard to sufficiency of the confidentiality claim. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims, wherever warranted and such information has been considered confidential and not disclosed to other interested parties. Wherever possible, parties providing information on confidential basis were directed to provide sufficient non-confidential version of the information filed on confidential basis. The



Authority made available the non-confidential version of the evidence submitted by various interested parties in the form of public file. The information related to imports, performance parameters and injury parameters of domestic industry has been made available in the public file. Business sensitive information has been kept confidential as per practice.

## **E. MISCELLANEOUS SUBMISSIONS**

### **E. 1 Submissions of other interested parties**

21. The other interested parties have made the following submissions on various issues:

- a. The Applicant has not brought any substantive evidence to prove condition for initiation of the investigation and has instead exaggerated imports and invented the injury. There are bare assertions and false statement with inaccurate and insufficient data.
- b. The users of Aniline are primarily small and medium scale units working in price sensitive and competitive market. The imposition of anti-dumping duty will impact it which is already facing slowdown and increased cost of input chemicals.
- c. Period of investigation is a deviation of past practice of Authority. Even in recently initiated investigation of newsprint, Authority adopted a 9-month period of investigation when petitioner requested for 6-month period of investigation. The same is also a deviation from the practice followed by other members.
- d. As per para 5.10 of the SOP, period of investigation should be 12 months. No justification has been provided by the Authority.
- e. 6-month period of investigation has been chosen to hide the effects of shutdown due to maintenance of 27 days by the domestic industry in the year 2018-19. As a result, the period of investigation has been left to only for 5 months.
- f. The present case does not reflect justification to consider a 6-month period of investigation. At least a year period should be taken for considering all cyclic impacts associated with the business to examine injury.
- g. The inappropriateness of POI is also visible from the fluctuating monthly import prices. The petitioner has claimed a decline in import price in the period of investigation, however over the period of investigation the price has increased by 6% which shows inappropriateness of shorter period for injury analysis.
- h. Shortage of raw material would lead to disruption in production of downstream products. Duties may be recommended only if the capacities of local producers are sufficient to cater demand.
- i. Downstream products are also manufactured in China which are being shipped to India and other customers of Indian producers in European Union and Asia.
- j. The effects of Covid-19 pandemic are visible on the dyestuff producers in the SME/MSME sector and any additional duty on the inputs shall lead to permanent closure of many units.
- k. The Applicant cannot cater the demand and therefore the imports will continue to happen. The duty would allow the Applicant to manipulate the price and increase its profits.

### **E. 2 Examination by the Authority**

22. The Authority has considered the views of interested parties, as under:-

- a. Regarding the submission of other interested parties on the selection of POI of 6 months, the Authority notes that the adoption of 6 months as period of investigation is not inconsistent with the Rules. The domestic industry substantiated the need for considering April 2019 to Sept 2019 (6 months) as the period of investigation (POI). The Authority accepted the same, being satisfied with the reasons given by the domestic industry. The Authority considers that 6 months POI in the present case is

appropriate as the decline in import prices from subject country is steep in April-Sept, 19. The petition in the present case was filed on 27<sup>th</sup> December, 2019 and therefore data for the period after Sept., 2019 was not available at the stage of initiation. The purpose of an antidumping investigation is to examine whether the product has been dumped and whether such dumping has caused material injury to the domestic industry. Thus, the Authority notes that the POI chosen for the case is consistent with the legal position at the time of initiation and the practice being followed by the Authority. It is further noted that the Rules have been amended vide Customs Notification no. 9/2020-customs dated 2<sup>nd</sup> February 2020 wherein Rule 2(da) and Explanation to Rule 22 have been inserted, incorporating the following provisions:

*“The POI shall :-*

*(i) not be more than six months old as on the date of initiation of investigation.*

*(ii) be for a period of twelve months and for the reasons to be recorded in writing the designated authority may consider a minimum of six months or maximum of eighteen months.”*

It is noted that the above amendment has been carried out after the initiation of the present investigation. Nevertheless, the Authority had duly considered the justification provided by the Applicant for selection of April 2019 to Sept 2019 (6 months) as POI, as mentioned above.

- b. As regards shutdown for around a month reported in the annual report resulting in effectively curtailing the period of investigation to only 5 months, it is noted that the plant maintenance was conducted in the year 2018-19 and not in the period April 2019 to September 2019. Therefore, the period of investigation pertains to clear 6 months and is found to be appropriate in the given circumstances.
- c. The Authority notes that the demand supply gap in the country does not bar a domestic industry from seeking redressal from dumped imports. As held by the CESTAT in the matter of DSMI demitsu Limited vs. Designated Authority, demand-supply gap does not justify dumping. The foreign producers can always meet the Indian demand by selling the product at undumped prices. Even after the imposition of antidumping duty, the imports are not restricted in the country. Therefore, there is no basis for the claim that imposition of ADD can lead to shortage of the raw material for the downstream industry. The Authority notes that imposition of anti-dumping duty provides level playing field and does not prevent fair competition in the market. The Authority also notes the submission of the domestic industry that Aniline is produced and exported by many countries. The users are free to import the subject goods from any source.
- d. The Authority notes that the present investigation is for Aniline and not for its downstream product. The import of downstream product of Aniline does not affect the present case.
- e. The Authority notes that the investigation was initiated on the basis of sufficient prima facie evidence submitted by the Applicant.

#### **F. NORMAL VALUE, EXPORT PRICE AND DETERMINATION OF DUMPING MARGIN**

23. Under Section 9A(1)(c) of the Act, normal value in relation to an article means:

- (i) *the comparable price, in the ordinary course of trade, for the like article when meant for consumption in the exporting country or territory as determined in accordance with the rules made under sub-section (6); or*
- (ii) *when there are no sales of the like article in the ordinary course of trade in the domestic market of the exporting country or territory, or when because of the particular market situation or low volume of the sales in the domestic market of the exporting country or territory, such sales do not permit a proper comparison, the normal value shall be either-*

- (a) *comparable representative price of the like article when exported from the exporting country or territory or an appropriate third country as determined in accordance with the rules made under sub-section (6); or the cost of production of the said article in the country of origin along with reasonable addition for administrative, selling and general costs, and for profits, as determined in accordance with the rules made under sub-section (6):*
- (b) *Provided that in the case of import of the article from a country other than the country of origin and where the article has been merely transshipped through the country of export or such article is not produced in the country of export or there is no comparable price in the country of export, the normal value shall be determined with reference to its price in the country of origin."*

### **F.1 Submissions of the Domestic industry**

24. The submissions made by the domestic industry with regard to normal value, export price and dumping margin are as follows:
- a. Normal value of Chinese producers cannot be accepted unless the producers show that their accounts reasonably reflect the costs associated with the production and sale of the product under consideration, having regard to the provisions of Rule 7 and 8 of the Rules, provisions of Accession Protocol of China, and the practice being followed by the Designated Authority.
  - b. The normal value needs to be determined based on the surrogate country.
  - c. Barring China and European Union, the number of producers of the subject goods in other countries are very few.
  - d. The production capacity in European Union is almost at the same level as in China.
  - e. Only exports from European Union are more than 5% of exports to India.
  - f. Even on a comparison of GDP and GNI, there is no country except European Union which can be considered as an appropriate surrogate country.
  - g. European Union can be considered as an appropriate surrogate country for the purpose of determination of normal value.
  - h. Exports from Belgium to Germany constitute evidence of price of Aniline in a market economy third country.
  - i. The dumping margin is positive and significant.

### **F.2 Submissions made by other interested parties**

25. The submissions made by the interested parties with regard to normal value, export price and dumping margin are as follows:
- i. Normal value cannot be adopted on the basis of selling price from Belgium to Germany as it does not fulfil the requirement of Rule 7 – second option. An option could have been price from Belgium to countries including India as a basis of normal value.
  - ii. Price from Belgium to Germany amounts to intra country price and cannot be seen as price in European Union. Price considered is very high as compared to prices prevailing in European Union.
  - iii. It is inappropriate to consider EU as a surrogate country. Petitioner has failed to put proper claims as permissible in law.
  - iv. The Authority is requested to reconsider various propositions of the petitioner concerning normal value, presuming that Chinese producers may not be able to satisfy ME conditions.
  - v. Authority has issued a separate questionnaire to exporters from China PR seeking voluminous information from exporters with regard to market economy.

- vi. India must fulfil its obligation to WTO and recognize China PR as a market economy status. Surrogate country methodology for China PR expired from 11th December 2016. After the expiry of China's accession to WTO, it must be treated in same way as any other WTO member and regardless of the domestic law of a particular member, imports from China PR must be demonstrated on the basis of Chinese prices and costs.
- vii. In EU, most Aniline producers are also MDI manufacturers. Covestro has Aniline plant in Belgium and Germany and MDI plant in Germany and Spain. Covestro has to transfer Aniline from Belgium to Germany or Spain for MDI manufacturing. Such transfer price shall not be deemed as market price as Aniline is transferred within Covestro Group between affiliated parties. Similar situation applies to BASF, DOW, Huntsman and Borsodchem, except for CUF. The normal value cannot be considered on basis of the transactions between related entities.
- viii. CUF is the only producer of Aniline in EU which does not have MDI plant, hence Aniline cannot be transferred within CUF or its related parties which might be located in different countries unlike Covestro, BASF, DOW, Huntsman and Borsodchem do. CUF plant is located in Portugal only. For the purpose of normal value, sales of CUF (producer) by Portugal to Germany can be relied upon at best.
- ix. Para 13.18.2 of the Manual of SOP states that appropriate surrogate country may be relied after considering level of development of country and product under consideration.
- x. There is significant difference in the GDP - per capita income, GDP, GDP per person, consumer spending, GDP real growth rate, economy growth rate, economy growth, world trade growth and population between the two countries and hence they are not comparable.
- xi. On the basis of data presented in the petition, there is significant difference between the quantity and price of imports from China PR and European Union in India.
- xii. If the Authority does not agree with the submissions that Portugal to Germany prices should be considered as normal value, it is requested then that normal value for China PR can be constructed as per Para 7 of Annexure 1 of Rules. For this purpose, international prices of Benzene can be considered, consumption factor of raw material can be considered for participating producer, utilities cost can be worked out with the prevailing prices in China and interest rate as prevailing in the international market including China may be considered. Reasonable profit may also be added for the product under consideration exported to India from China.

### **F.3 Examination by the Authority**

#### **F.3.1 Determination of normal value and export price.**

##### **Market Economy Status for Chinese Producers**

26. Article 15 of China's Accession Protocol in WTO provides as follows: "Article VI of the GATT 1994, the Agreement on Implementation of Article VI of the General Agreement on Tariffs and Trade 1994 ("Anti-Dumping Agreement") and the SCM Agreement shall apply in proceedings involving imports of Chinese origin into a WTO Member consistent with the following:

*"(a) In determining price comparability under Article VI of the GATT 1994 and the Anti-Dumping Agreement, the importing WTO Member shall use either Chinese prices or costs for the industry under investigation or a methodology that is not based on a strict comparison with domestic prices or costs in China based on the following rules:*

*(i) If the producers under investigation can clearly show that market economy conditions prevail in the industry producing the like product with regard to the manufacture, production and sale of that product, the importing WTO Member shall use Chinese prices or costs for the industry under investigation in determining price comparability;*

*(ii) The importing WTO Member may use a methodology that is not based on a strict comparison with domestic prices or costs in China if the producers under*



*investigation cannot clearly show that market economy conditions prevail in the industry producing the like product with regard to manufacture, production and sale of that product.*

*(b) In proceedings under Parts II, III and V of the SCM Agreement, when addressing subsidies described in Articles 14(a), 14(b), 14(c) and 14(d), relevant provisions of the SCM Agreement shall apply; however, if there are special difficulties in that application, the importing WTO Member may then use methodologies for identifying and measuring the subsidy benefit which take into account the possibility that prevailing terms and conditions in China may not always be available as appropriate benchmarks. In applying such methodologies, where practicable, the importing WTO Member should adjust such prevailing terms and conditions before considering the use of terms and conditions prevailing outside China.*

*(c) The importing WTO Member shall notify methodologies used in accordance with subparagraph (a) to the Committee on Anti-Dumping Practices and shall notify methodologies used in accordance with subparagraph (b) to the Committee on Subsidies and Countervailing Measures.*

*(d) Once China has established, under the national law of the importing WTO Member, that it is a market economy, the provisions of subparagraph (a) shall be terminated provided that the importing Member's national law contains market economy criteria as of the date of accession. In any event, the provisions of subparagraph (a)(ii) shall expire 15 years after the date of accession. In addition, should China establish, pursuant to the national law of the importing WTO Member, that market economy conditions prevail in a particular industry or sector, the nonmarket economy provisions of subparagraph (a) shall no longer apply to that industry or sector."*

27. It is noted that while the provision contained in Article 15 (a) (ii) have expired on 11.12.2016, the provision under Article 2.2.1.1 of WTO read with obligation under 15 (a) (i) of the Accession protocol require criterion stipulated in para 8 of the Annexure I of the Rules to be satisfied through the information/data to be provided in the supplementary questionnaire on claiming the market economy status. It is noted that since the responding producers/ exporters from China PR have not submitted response to questionnaire in the form and manner prescribed, the normal value computation is required to be done as per provisions of para 7 of Annexure I of the Rules.
28. Accordingly, the normal value for all the producers/exporters from the subject country have been determined as below.

#### **Normal Value for all Producers in China PR.**

29. As none of the producers from China PR have claimed determination of normal value on the basis of their own data/information, the normal value has been determined in accordance with para 7 of Annexure I of the Rules which reads as under:.

*In case of imports from non-market economy countries, normal value shall be determined on the basis if the price or constructed value in the market economy third country, or the price from such a third country to other countries, including India or where it is not possible, or on any other reasonable basis, including the price actually paid or payable in India for the like product, duly adjusted if necessary, to include a reasonable profit margin. An appropriate market economy third country shall be selected by the designated authority in a reasonable manner, keeping in view the level of development of the country concerned and the product in question, and due account shall be taken of any reliable information made available at the time of selection. Accounts shall be taken within time limits, where appropriate, of the investigation made in any similar matter in respect of any other market economy third country. The parties to the investigation shall be informed without any unreasonable delay the aforesaid selection of the market economy third country and shall be given a reasonable period of time to offer their comments.*

30. The Authority had also sought comments from the other interested parties on European Union as a surrogate country for China. The extract of initiation notification is as under-

*9. All interested parties are advised to offer their comments on this issue within 30 days from the date of issuance of initiation notification. Pending detailed examination of the Page 3 of 6 claim of EU as a surrogate country for China for this investigation, the Authority, for the purpose of initiation of the present investigation, has taken the selling price from Belgium to Germany for determining the normal value of China PR.*

31. With regard to comments from the other interested parties on European Union as a surrogate country for China, it is noted that within the time line of 30 days given by the Authority in the initiation notification, none of the interested party gave their comments on the proposition of considering EU as a surrogate country for China. However, the Dyestuffs Manufacturers' Association of India (DMAI) and Wanhua Group have raised concerns over the proposed methodology, after the given time period.
32. One of the interested parties has contended that the normal value in the instant case should be determined on the basis of price paid or payable in India, duly adjusted.
33. Since there are rival submissions with regard to consideration of EU as an appropriate market economy third country, for the purpose of the preliminary findings, normal value has been determined on the basis of price paid or payable in India, duly adjusted to include profit, which has been determined considering cost of production in India, after addition for selling, general & administrative expenses and reasonable profits. The normal value so determined is given below in dumping margin table.

#### **Determination of Export Price**

**For M/s Wanhua Chemical Group Co., Limited, M/s Wanhua Chemical (Hong Kong) Co. and M/s Kempar Energy Pte. Limited, Singapore.**

34. The Authority notes that following producers/exporters have filed questionnaire responses:
- M/s Wanhua Chemical Group Co., Limited (Wanhua)
  - M/s Wanhua Chemical (Hong Kong) Co., Limited, Hong Kong.
  - M/s Kempar Energy Pte. Limited, Singapore.
  - M/s Wanhua Chemical (Yantai) Trading Co., Limited
  - M/s Wanhua Chemical (Ningbo) Co., Limited
  - M/s Wanhua Chemical (Ningbo) Trading Co., Limited
35. It is noted that during POI, M/s Wanhua Chemical Group Co., Ltd., (producer/exporter) is a producer of the subject goods in China PR, and has exported the subject goods through related and unrelated traders to customers in India. The responding producer/exporter has given details of the exports of subject goods to India in Appendix 3C of the exporters' questionnaire response. The responding producer/exporter has also clarified that Appendix 3A is not applicable in their case because there are no direct sales to Indian customers. It is noted from the response that M/s Wanhua Chemical Group Co., Ltd., has exported \*\*\*\* MT subject goods to India through M/s Wanhua Chemical (Hong Kong) Co., Ltd., Hong Kong (Trader). M/s Wanhua Chemical (Hong Kong) Co., Ltd., Hong Kong, has in-turn exported the same to India through M/s Kempar Energy Pte. Ltd., Singapore. The other related producer M/s Wanhua Chemical (Ningbo) Co., Limited has not exported the subject goods to India during POI directly or through its related traders. It is further noted that M/s Wanhua Chemical (Ningbo) Co., Ltd., M/s Wanhua Chemical (Yantai) Trading Co., Ltd., and M/s Wanhua Chemical (Ningbo) Trading Co., Limited, are not involved in exports to India.
36. For the exports to India, the producer/exporter has claimed adjustments on account of port and other related expenses, transportation via ship and Non-Refundable VAT. Further, bank charges and credit expenses claimed by the related exporter M/s Wanhua Chemical (Hong Kong) Co., Ltd., Hong Kong have also been provisionally considered to arrive at ex-factory export price. The Authority has relied upon the details of the exports given in the questionnaire response



filed by the producer/exporter for the purpose of Preliminary findings subject to verification of information. The adjustments towards port and other related expenses, transportation via ship and Non-Refundable VAT, bank charges and credit expenses of the trader have been provisionally accepted for the purpose of preliminary findings. Accordingly, the Authority has provisionally determined the net export price, as mentioned in the dumping margin table below.

**For all other producers/exporters from China PR**

37. The export price for all other producers and exporters who has not participated in the present investigation has been determined as per facts available considering after allowing due adjustments for ocean freight, marine insurance, credit cost, inland & port charges and VAT refund and the same has been mentioned in the dumping margin table.

**F.3.2 Dumping Margin**

38. Considering the normal value and export price for subject goods, the dumping margins have been provisionally determined as follows:

Country	Name of Producer	Normal Value/ CNV (US\$/MT)	Export Price (US\$/MT)	Dumping Margin US\$/MT	Dumping Margin %	Dumping Margin Range
China PR	Wanhua Chemical Group Co., Limited	****	****	****	****	20-40
	Other Producers	****	****	****	****	40-60

**G. INJURY AND CAUSAL LINK**

**G.1 Submissions made by the Domestic Industry**

39. Following submissions have been made by the domestic industry with regard to injury and causal link:
- The demand of the subject goods has declined in the period of investigation. However, the demand is still more than the capacity and hence fall cannot cause injury to the domestic industry.
  - The imports of the subject goods have increased significantly from the subject country in absolute terms and in relation to production and consumption.
  - The import prices have steeply declined in the period of investigation.
  - The subject imports are undercutting the prices of the domestic industry.
  - The selling price of the domestic industry has declined whereas the cost of sales of the domestic industry has increased.
  - The imports have depressed the prices of the domestic industry.
  - The capacity utilization of the domestic industry is low.
  - The production and the sales of the domestic industry have seen a fall of more than 51% and 43% as compared to the base year.
  - The profitability of the domestic industry has been severely impacted in the period of investigation as it is running in losses.
  - Cash profits and the return on investment of the domestic industry have turned negative in the period of investigation.

- k. The domestic industry has lost its market share of around 28% over the injury period. The market share of the subject country imports has taken an increase from around 46% to 78%.
- l. The average inventories with the domestic industry are significant representing around \*\*\*\*% of the annual sales value.
- m. The domestic industry has recorded a negative growth in all the parameters.
- n. The subject imports have increased at an alarming rate threatening to cause further injury.
- o. There are significant capacities with the producers in the subject country.
- p. The imports have had a depressing effect on the prices of the domestic industry and are likely to make way for increase in demand of subject imports

## **G.2 Submissions made by other interested parties**

40. The submissions made by the interested parties with regard to injury are as follows:

- a. When price undercutting was at highest level, the domestic industry was earning very good profits. However, when the price undercutting at lowest level, it has suffered losses.
- b. Around 70,000-75,000 MT of subject goods is imported because production capacity in India is lower than demand in India.
- c. Imports are made from China as they are most competitively priced because of economies of scale.
- d. The fact that domestic industry was making high profits when undercutting was 10-20% in the base year and made losses when it was 0-10% in the period of investigation shows the distortion on account less than 12 months of period of investigation.
- e. Price undercutting was negative for at least 2 months in the period of investigation which shows that landed price of imports is not a factor of injury and losses cannot be on account of pressure of imports.
- f. Domestic industry was operating at capacity utilization around 108% in 2018-19 and 119% in the period of investigation. Even after a dip, it would have been at a very reasonable level. Further, slight correction from past high numbers is not a situation suggesting injury.
- g. Temporary movements in prices due to economic slowdown, fluctuations in input cost based on crude, etc. cannot be termed as injury to impose anti-dumping duty for another 5 years.
- h. Injury could be self-inflicted and could be caused due to shut down by domestic industry.
- i. Sudden decline in the economic trend during the period of investigation raises serious question about data as everything was normal in the injury period between 2016-17 to 2018-19
- j. There is a decline in both the domestic sales (43%) and the export sales (33%) in the period of investigation as compared to the base year which shows that injury may be due to some other reason.
- k. The increase in cost of sales and decrease in selling price is due to low production and capacity utilization, not due to imports from subject country.
- l. Article 3.5 of the Agreement requires the Authority to examine factors other than dumping causing injury.
- m. Appellate body in US-Hot Rolled Steel, ruled that the examination by panel in US-Norwegian Salmon AD was erroneous (Panel in US Atlantic had held that there is no need to isolate the injury due to the other factors)
- n. Petition fails to address a number of issues which have an impact on the performance of the domestic industry.

**G.3 Examination by the Authority**

41. Rule 11 of Rules read with Annexure II provides that an injury determination shall involve examination of factors that may indicate injury to the Domestic Industry, "*.... taking into account all relevant facts, including the volume of dumped imports, their effects on prices in the domestic market for like articles and the consequent effect of such imports on domestic producers of such articles....*". In considering the effect of the dumped imports on prices, it is considered necessary to examine whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared with the price of the like article in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increases, which otherwise would have occurred, to a significant degree. For the examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry in India, indices having a bearing on the state of the industry such as production, capacity utilization, sales volume, inventory, profitability, net sales realization, the magnitude and margin of dumping, etc. have been considered in accordance with Annexure II of the Rules.

**G.3.1. Volume Effect of Dumped Imports on Domestic Industry****a. Assessment of Demand / Apparent Consumption**

42. The Authority has taken into consideration, for the purpose of the present investigation, demand or apparent consumption of the product in India as the sum of domestic sales of the Indian Producers and imports from all sources.

SN	Particulars	Unit	2016-17	2017-18	2018-19	POI	
						Actual	Annualized
1	Sales of Domestic Industry	MT	41,604	41,339	34,813	11,952	23,904
2	Trend	Indexed	100	99	84	57	57
3	Subject Imports	MT	40,523	48,918	66,748	46,767	93,534
4	Trend	Indexed	100	121	165	231	231
5	Other countries imports	MT	4,127	16,441	21,370	823	1,645
6	Trend	Indexed	100	398	518	40	40
7	Total demand	MT	86,253	1,06,697	1,22,931	59,542	1,19,083
8	Trend	Indexed	100	124	143	138	138

43. The demand for the subject goods has increased over the injury period with marginal decline in period of investigation.

**b. Increase in imports from the subject country in absolute and relative terms**

44. With regard to the volume of the imports, the Authority is required to consider whether there has been a significant increase in the imports, either in absolute terms or relative to production or consumption in India. Factual position is as follows :-

SN	Particulars	Unit	2016-17	2017-18	2018-19	POI	
						Actual	Annualised
1	Imports from China PR	MT	40,523	48,918	66,748	46,767	93,534
2	Import from Other Countries	MT	4,127	16,441	21,370	823	1,645
3	Total imports	MT	44,650	65,358	88,118	47,590	95,179
4	<b>Subject Imports in relation to</b>						
A	Total imports	%	91%	75%	76%	98%	98%
B	Indian Production	%	****	****	****	****	****

C	Trend	Indexed	100	119	180	472	472
D	Indian Demand	%	47%	46%	54%	79%	79%
E	Trend	Indexed	100	98	116	167	167

45. It is noted that the subject imports have increased significantly in absolute terms over the injury period. The subject imports have also increased in relative terms. The imports have increased in relation to total imports, production and consumption in India. Further, imports show increase as compared to both base year and immediate previous year. It is further noted that the subject import have shown massive growth in relation to the Indian production as compared to both base year and immediate previous year.

### G.3.2 Price Effect of the Dumped Imports on the Domestic Industry

46. With regard to the effect of the dumped on the prices of the domestic industry, it is required to be examined whether there has been a significant price undercutting by the alleged dumped imports as compared to the price of the like products in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices or prevent price increases, which otherwise would have occurred in the normal course. The impact on the prices of the domestic industry on account of the dumped imports from subject country has been examined with reference to price undercutting, price underselling, price suppression and price depression, if any. For the purpose of this analysis, cost of production, net sales realization (NSR) and non-injurious price (NIP) of the domestic industry have been compared with landed price of imports of the subject goods from the subject country.

#### a. Price Undercutting

47. For the purpose of price undercutting analysis, net selling price of the domestic industry has been compared with the landed value of imports from the subject country. Accordingly, the undercutting effects of the imports from the subject country work out as follows:

SN	Particulars	Unit	2016-17	2017-18	2018-19	POI	
						Actual	Annualised
1	Net Sales Realisation	₹/MT	****	****	****	****	****
2	Trend	Indexed	100	125	121	91	91
3	Landed Price	₹/MT	69,424	95,464	94,632	69,255	69,255
4	Trend	Indexed	100	138	136	100	100
5	Price undercutting	₹/MT	****	****	****	****	****
6	Trend	Indexed	****	****	****	****	****
7	Price undercutting	%	****	****	****	****	****
8	Price undercutting	Range	10-20%	0-10%	0-10%	0-10%	0-10%

48. It is seen that the imports from subject country are entering at a price below the domestic selling price of the domestic industry, resulting in positive price undercutting.

#### b. Price Suppression and Depression

49. In order to determine whether the imports are depressing the domestic prices or whether the effect of such imports was to suppress prices to a significant degree or prevent price increases which otherwise would have occurred in normal course, the changes in the costs and prices over the injury period, were compared alongwith import prices. The Table below shows factual position:

SN	Particulars	Unit	2016-17	2017-18	2018-19	POI	
						Actual	Annualised
1	Cost of Sales	₹/MT	****	****	****	****	****
2	<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>109</i>	<i>118</i>	<i>113</i>	<i>113</i>
3	Selling price	₹/MT	****	****	****	****	****
4	<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>125</i>	<i>121</i>	<i>91</i>	<i>91</i>
5	Landed Value	₹/MT	69,424	95,464	94,632	69,255	69,255
6	<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>138</i>	<i>136</i>	<i>100</i>	<i>100</i>

50. It is seen that

- Imports from the subject country were earlier at a price above cost of sales of the domestic industry upto 2018-19. However, imports were at a price below cost of sales of the domestic industry in the POI. It is also noted that from 2017-18, there has been a significant decline in the selling prices of subject goods while cost of sales increased.
- Whereas cost of sales, selling price and import price declined in POI, the decline in landed price of imports was far higher and significant as compared to cost of sales. The domestic industry was also forced to reduce the prices far beyond the decline in cost of sales.
- Thus, the imports of subject goods from subject country has prevented price increases which otherwise would have occurred due to increase in cost of production. The domestic industry has suffered price suppression on account of import of subject goods from subject country. Further, the subject imports have depressed the prices of the domestic industry to a very significant extent.

#### Price underselling

51. The non-injurious price (NIP) of the Domestic Industry has been determined and compared with the landed value of the subject goods to arrive at the extent of price underselling. The NIP of the product under consideration has been determined by adopting the verified information/data relating to the cost of production for the period of investigation on the basis of principles mentioned in Annexure III of the Rules. The analysis shows that during the period of investigation, the landed value of subject imports was below the non-injurious price of the Domestic Industry, as can be seen from the table below, demonstrating positive price underselling effect:

SN	Particulars	Unit	POI
1	Landed Price	Rs/MT	69,255
2	NIP	Rs/MT	****
3	Price underselling	Rs/MT	****
4	Price underselling	%	****
5	Price underselling	Range	0-20

52. It is seen that the landed price of the subject goods from the subject country was lower than the NIP determined for the domestic industry. The price underselling for China PR is positive and significant.

#### G.3.3. Economic Parameters of the Domestic Industry

53. Annexure II to the Rules provide that the examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry should include an objective and unbiased evaluation of all relevant economic factors and indices having a bearing on the state of the industry, including actual and

potential decline in sales, profits, output, market share, productivity, return on investments or utilization of capacity; factors affecting domestic prices, the magnitude of the margin of dumping; actual and potential negative effects on cash flow, inventories, employment, wages, growth, ability to raise capital investments. The various injury parameters relating to the domestic industry are discussed below. The Authority has examined the injury parameters objectively taking into account various facts and arguments made by the interested parties in their submissions.

**a. Production, Capacity, Capacity utilization and Sale**

54. Capacity, production, sales and capacity utilization of the Domestic Industry over the injury period is given in the table below: -

S.No.	Particulars	Unit	2016-17	2017-18	2018-19	POI	
						Actual	Annualised
1	Capacity	MT	****	****	****	****	****
2	Trend	Indexed	100	100	100	100	100
3	Production	MT	****	****	****	****	****
4	Trend	Indexed	100	101	91	49	49
5	Capacity utilization	%	****	****	****	****	****
6	Trend	Indexed	100	101	91	49	49
7	Domestic Sales	MT	41,604	41,339	34,813	11,952	23,904
8	Trend	Indexed	100	99	84	57	57

55. It is seen that

- The capacity of the domestic industry has remained constant over the injury period.
- The production and capacity utilization of the domestic industry marginally increased in 2017-18, but declined thereafter, with a significant decline in the POI.
- The sales of the domestic industry declined throughout the injury period, with a significant decline in the Period of investigation (POI)

56. It is thus seen that production, capacity utilization and sales of the domestic industry declined in 2018-19 and thereafter in the POI. The decline in these parameters is quite significant and the same appears to be a consequence of increase in imports from subject country.

**b. Market Share**

57. Market share of the domestic industry over the injury period is shown in table below:

SN	Particulars	Unit	2016-17	2017-18	2018-19	POI	
						Actual	Annualised
1	Domestic Industry	%	48%	39%	28%	20%	20%
2	Trend	Indexed	100	80	59	42	42
3	Subject Imports	%	47%	46%	54%	79%	79%
4	Trend	Indexed	100	98	116	167	167
5	Other countries	%	5%	15%	17%	1%	1%
6	Trend	Indexed	100	322	363	29	29
7	Total	%	100	100	100	100	100



58. It is seen that the market share of the domestic industry has consistently declined over the injury period. The market share of the domestic industry declined by 58 basis points over the injury period, when the share of subject imports in demand increased by 67 basis points over the injury period. The market share of all other countries also declined over the period.

**c. Profitability, return on investment and cash profits**

59. Profitability, return on investment and cash profits of the domestic industry over the injury period is given in the table below:

SN	Particulars	Unit	2016-17	2017-18	2018-19	POI	
						Actual	Annualised
1	Cost of sales	₹/MT	****	****	****	****	****
2	Trend	Indexed	100	109	118	113	113
3	Selling price	₹/MT	****	****	****	****	****
4	Trend	Indexed	100	125	121	91	91
5	Profit per unit	₹/MT	****	****	****	****	****
6	Trend	Indexed	100	205	132	(26)	(26)
7	Total Profit/(Loss)	Rs. Lacs	****	****	****	****	****
8	Trend	Indexed	100	203	111	(15)	(15)
9	Cash Profit	Rs. Lacs	****	****	****	****	****
10	Trend	Indexed	100	202	110	(14)	(14)
11	Profit before Interest	Rs. Lacs	****	****	****	****	****
12	Trend	Indexed	100	198	107	(14)	(14)
13	Return on Capital Employed	%	****	****	****	****	****
14	Trend	Indexed	100	204	106	(18)	(18)

60. It is seen that

- The domestic industry was earning profits till 2018-19. While profit per unit increased in 2017-18, the same declined in 2018-19, and thereafter in POI. Profitability of the domestic industry declined so significantly in the POI that the domestic industry suffered financial losses in the POI.
- The cash flow and return on investment followed the same trend as that of profits. The cash profits and return on investment increased in 2017-18 and declined thereafter till the POI so significantly that the domestic industry suffered cash losses and negative return on investment in the POI.

**d. Employment, Wages and Productivity**

61. Employment, wages and productivity of the domestic industry over the injury period is given in the table below.

SN	Particulars	Unit	2016-17	2017-18	2018-19	POI	
						Actual	Annualized
1	No of Employees	Nos	****	****	****	****	****
2	Trend	Indexed	100	100	104	103	103
3	Salary and Wages	Rs. Lacs	****	****	****	****	****
4	Trend	Indexed	100	102	129	52	104
5	Productivity per day	MT/Day	****	****	****	****	****
6	Trend	Indexed	100	101	91	49	49

62. It is seen that performance of the domestic industry has not changed significantly in respect of employment and wages. The productivity per day has declined in the POI because of decline in production.

**e. Inventories**

63. Inventory position with the domestic industry over the injury period is given in the table below:

SN	Particulars	Unit	2016-17	2017-18	2018-19	POI	POI (A)
1	Average Inventory	MT	****	****	****	****	****
2	Trend	Indexed	100	26	380	479	479

64. It is seen that the average inventories with the domestic industry have increased significantly in last two periods including the period of investigation as compared to the first two periods of the injury period.

**f. Growth**

65. The growth of the domestic industry in terms of production, capacity utilization domestic sales volume, inventories, profits, cash profits and return on investment is as per below table-

SN	Particulars	Unit	2017-18	2018-19	POI Annualized
1	Production	Y/Y	1%	-10%	-46%
2	Domestic Sales	Y/Y	-1%	-16%	-31%
3	Capacity Utilization	Y/Y	1%	-10%	-46%
4	Average Inventory	Y/Y	-74%	1362%	26%
5	Market Share of DI	Y/Y	-20%	-27%	-29%
6	Profit/(Loss)	Y/Y	103%	-46%	-113%
7	Cash Profit	Y/Y	102%	-45%	-112%
8	PBIT	Y/Y	98%	-46%	-113%
9	Return on Capital Employed	Y/Y	104%	-48%	-117%

**g. Magnitude of Dumping Margin**

66. Magnitude of dumping is an indicator of the extent to which the imports are being dumped in India. The investigation has shown that dumping margin is positive and significant in the investigation period.

**h. Ability to Raise Capital Investment**

67. The domestic industry is suffering financial losses in the period of investigation. With the competition being faced by the domestic industry because of the imports, the operations of the industry have been impacted which has affected the ability to raise capital investment. However, it may be added that the domestic industry is a multi-product company and therefore ability to raise capital investment is not governed based on the performance of the product under consideration (PUC) alone.

**i. Factors affecting domestic prices**

68. The import prices are directly affecting the prices of the domestic industry in the market. It is noted that the landed value of the subject goods from subject country is not only below its net selling price but also the non-injurious price of the domestic industry. Further the landed prices of subject imports have depressed the prices of the domestic industry leading to financial losses. The imports of subject goods from third countries are negligible in volumes and not injuring to the domestic industry. Demand for the product under consideration is far higher than the capacities in the country and cannot be the reason of injury to the domestic industry. Dumped

imports are impacting the prices of the product in the market. Thus, it can be provisionally concluded that the principal factor affecting the domestic prices is the dumped imports of subject goods from the subject country.

69. The Authority has taken note of various submissions made by the Domestic Industry and other Interested parties on injury and causal link, and has analyzed the same considering the facts available on record and applicable laws. The injury analysis made by the Authority in the preceding paras ipso facto addresses submissions made by the domestic industry and other interested parties.
70. It is seen that the growth of the domestic industry in terms of production, capacity utilization, domestic sales volume, inventories, profits, cash profits and return on investment was adverse and negative in the POI.
71. As regards the contention that there is no co-relation between price undercutting and profits, the Authority notes that positive price undercutting does not always mean that the domestic industry performance should always decline. Further, high price undercutting implies that the selling price of the domestic industry was higher than the import price. It is noted that during the POI, because of steep decline in the import price, the domestic industry has been forced to reduce its selling prices significantly. Further, despite reducing prices, the domestic industry has lost significant sales volumes. Decline in sales volumes despite reduction in selling price because of price undercutting and consequent increase in import volumes shows that the domestic industry reduced its prices, and still lost volumes, while subject imports were undercutting domestic industry prices and their import volumes also increased.
72. As regards the contention that Chinese imports are due to economies of scale leading to competitively priced, the Authority notes that the dumping margin is positive considering the normal value as proposed by the Applicant, and the constructed normal value (CNV) as determined by the Authority for the purpose of provisional findings. This fact shows that subject imports have entered into this country at dumped prices.
73. As regards negative price undercutting in at least two months of the POI, the authority notes that the price undercutting is required to be determined for the investigation period. It is quite possible that price undercutting is positive in some import transactions or months and negative in some other import transactions or months. The Authority is however required to determine weighted average price undercutting for the entire investigation period.
74. As regards arguments about lower production capacity of domestic industry, it is noted that the capacity utilisation of the domestic industry declined by about 50% over the injury period which is quite significant.
75. As regards fluctuations in input cost based on crude etc., the Authority notes that no verifiable information has been provided showing that such factors affected export price and did not affect normal value.
76. As regards alleged plant shut down, it is seen that production and capacity utilisation of the domestic industry declined by about 50%. Further, the Authority examined the trend of inventories with the domestic industry. It is seen that the domestic industry invariably had inventories throughout the period thus clearly showing that the decline in sales is not due to possible absence of production.
77. As regard the contention that the deterioration is only in the POI, the Authority notes that the performance of the domestic industry deteriorated even in 2018-19 in respect of production, capacity utilisation, domestic sales, market share, profit per unit, total profit, cash profit, inventories. The deterioration that started in 2018-19 continued further and intensified in POI.

#### **H. INJURY MARGIN**

78. The Authority has determined Non-Injurious Price (NIP) for the domestic industry on the basis of principles laid down in the Rules read with Annexure III, as amended. The non-injurious price of the product under consideration has been determined by adopting the information/data relating to the cost of production provided by the domestic industry and duly certified by the

practicing cost accountant for the period of investigation. The non-injurious price has been considered for comparing the landed price from the subject country for calculating injury margin. For determining the non-injurious price, the best utilisation of the raw materials by the domestic industry over the injury period has been considered. The same treatment has been carried out with the utilities. The best utilization of production capacity over the injury period has been considered. It is ensured that no extraordinary or non-recurring expenses were charged to the cost of production. A reasonable return (pre-tax @ 22%) on average capital employed (i.e. average net fixed assets plus average working capital) for the product under consideration was allowed as pre-tax profit to arrive at the non-injurious price as prescribed in Annexure III of the Rules and being followed.

79. For all the non-cooperative producers/exporters from the subject countries, the Authority has determined the landed price based on facts available.
80. Based on the landed price and non-injurious price determined as above, the injury margin for producers/exporters has been determined by the Authority and the same is provided in the table below:

Country	Name of Producer	Non-Injurious Price (US\$/MT)	Landed Value (US\$/MT)	Injury Margin US\$/MT	Injury Margin (%)	Injury Margin % (Range)
China PR	Wanhua Chemical Group Co., Limited	****	****	****	****	0-20
	Others	****	****	****	****	0-20

#### j. Conclusions on Injury

81. The examination of the imports of the subject product and performance of domestic industry shows that the volume of imports has increased in absolute terms as well as in relation to production and demand in India. The imports are undercutting the prices of the domestic industry, and the price underselling is also positive. The imports of subject goods from subject country has prevented price increases which otherwise would have occurred due to increase in cost of production. The domestic industry has suffered price suppression on account of import of subject goods from subject country. Further, the subject imports have depressed the prices of the domestic industry to a very significant extent.
82. It is also noted that Production, capacity utilization and domestic sales of the domestic industry declined over the injury period, with significant decline in the POI. The market share of the domestic industry has declined over the injury period with significant decline in the POI. At the same time, market share of subject imports from subject country has increased significantly. It is also noted that the domestic industry is faced with significant inventories.
83. The profitability of the domestic industry declined significantly over the injury period, and the domestic industry suffered financial losses in the period of investigation. The performance of the domestic industry deteriorated in respect of cash flow, PBIT and return on investment. The domestic industry suffered cash losses and negative return on investment in the period of investigation. Further, growth of the domestic industry became negative in the POI in respect of a number of injury parameters.
84. In view of above, the Authority provisionally concludes that the domestic industry has suffered material injury.

#### I. NON-ATTRIBUTION ANALYSIS

85. As per the Rules, the Authority, inter alia, is required to examine any known factors other than the dumped imports which at the same time are injuring the domestic industry, so that the

injury caused by these other factors may not be attributed to the dumped imports. Factors which may be relevant in this respect include, inter alia, the volume and prices of imports not sold at dumped prices, contraction in demand or changes in the patterns of consumption, trade restrictive practices of and competition between the foreign and domestic producers, developments in technology and the export performance and the productivity of the domestic industry. It has been examined below whether factors other than dumped imports could have contributed to the injury to the domestic industry.

86. The other interested parties have submitted that the injury suffered by the Applicant is due to other reasons and not due to the imports from the subject country. The Authority notes that the interested parties have not presented any verifiable evidence establishing that the domestic industry has suffered injury due to factors other than dumped imports. Even though the claims made by the opposing interested parties are mere assertions, the same have been examined based on information available on record.

**a. Volume and prices of imports from third countries**

87. Imports from subject country account for around 98% share in the imports. Thus, it cannot be said that imports from other countries are causing injury.

**b. Demand for the product**

88. Demand of the subject goods has increased over the injury period with marginal decline in the period of investigation when compared to the preceding year. However, demand in the POI was significantly higher than the demand in base year. The decline in demand cannot be a reason for the injury suffered by the domestic industry.

**c. Export performance**

89. The injury information examined hereinabove relates only to the performance of the domestic industry in terms of its domestic market. Thus, the injury suffered cannot be attributed to the export performance of the domestic industry.

**d. Development in technology**

90. No evidence has been brought by any interested parties about existence of significant changes in the technology that could have caused injury to the domestic industry.

**e. Performance of other products being produced and sold by the domestic industry**

91. The Authority has only considered data relating only to the performance of the subject goods. Therefore, performance of other products produced and sold are not a possible cause of the injury to the domestic industry.

**f. Changes in the pattern of consumption**

92. There have been no material changes in the pattern of consumption of the product under consideration. Hence, changes in the pattern of consumption have not caused injury to the domestic industry.

**g. Trade restrictive practices**

93. The import of the subject goods is not restricted in any manner and the same are freely importable in the country. No evidence has been submitted by any interested party to suggest that the conditions of competition between the foreign and the domestic producers have undergone any change.

**J. CONCLUSION ON CAUSAL LINK**

94. It is thus noted that other known factors listed under the Rules do not show that the domestic industry could have suffered injury due to these other factors. The Authority has also examined whether the dumping of the product has caused injury to the domestic industry. The following parameters show that material injury to the domestic industry has been caused by dumped imports:



- a. Imports of the subject goods from subject country have increased in absolute terms as well as in relation to production and consumption.
- b. The market share of subject imports has increased, while the share of domestic industry has declined over the same period. While the demand has also reduced, the fall in market share of the domestic industry is more than the fall in demand.
- c. There is price depression due to low priced dumped imports coming into India.
- d. The dumped imports are undercutting the prices of the domestic industry. The Price underselling is significant and positive.
- e. As a result, the production and sales of the domestic industry have declined over the period.
- f. The profits, cash profits and return on capital employed of the domestic industry have turned negative in the period of investigation.

**K. INDIAN INDUSTRY'S INTEREST AND OTHER ISSUES**

95. The Authority recognizes that the imposition of anti-dumping duties might affect the price levels of the product in India. However, fair competition in the Indian market will not be reduced by the imposition of anti-dumping measures. On the contrary, imposition of anti-dumping measures would remove the unfair advantages gained by dumping practices, prevent the decline of the domestic industry and help maintain availability of wider choice to the consumers of the subject goods. The purpose of anti-dumping duties, in general, is to eliminate injury caused to the domestic industry by the unfair trade practices of dumping so as to re-establish a situation of open and fair competition in the Indian market, which is in the general interest of the country. Imposition of anti-dumping duties, therefore, would not affect the availability of the product to the consumers. The Authority notes that the imposition of the anti-dumping measures would not restrict imports from the subject countries in any way, and therefore, would not affect the availability of the product to the consumers.

**L. CONCLUSION & RECOMMENDATIONS**

96. After examining the submissions made by the interested parties and issues raised and considering the facts on record, it is noted that:
- a. The product under consideration that has been exported to India from the subject country at dumped prices.
  - b. The domestic industry has suffered material injury.
  - c. The injury to the domestic industry has been caused by the dumped imports from subject country.
97. The Authority notes that the investigation was initiated and notified to all interested parties and adequate opportunity was given to the domestic industry, exporters, importers and other interested parties to provide positive information on the aspect of dumping, injury and causal link. Having initiated and conducted the investigation into dumping, injury and causal link in terms of the provisions laid down under the Rules, the Authority is of the view that imposition of provisional duty is required to offset dumping and injury, pending completion of the investigation. Therefore, Authority considers it necessary and recommends imposition of provisional anti-dumping duty on imports of subject goods from the subject country.
98. In terms of provision contained in Rule 17(1) (b) read with Rule 4(d) of the Rules, the Authority recommends imposition of anti-dumping duty equal to the lesser of margin of dumping and the margin of injury, so as to remove the injury to the Domestic Industry. Accordingly, definitive anti-dumping duty equal to the amount mentioned in Column 7 of the duty table below is recommended to be imposed from the date of the Notification to be issued by the Central Government, on all imports of subject goods originating in or exported from subject country.



Duty Table

SN	Heading/ Subheading	Description of Goods	Country of Origin	Country of Export	Producer	Duty	Unit	Currency
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	29214110	Aniline or aniline oil	China PR	Any country including China PR	Wanhua Chemical Group Co., Limited	65.91	MT	USD
2	29214110	Aniline or aniline oil	China PR	Any country including China PR	Any producer other than mentioned in S.No. 1	150.80	MT	USD
3	29214110	Aniline or aniline oil	Any country other than China PR	China PR	Any	150.80	MT	USD

**M. FURTHER PROCEDURE**

99. The procedure as below would be followed subsequent to notifying the preliminary findings:-

- (i) The Authority invites comments on these provisional findings from all the interested parties and the same, considered relevant by the Authority, would be considered in the final finding.
- (ii) Domestic Industry, exporters, importers and other interested parties known to be concerned are being addressed separately by the Authority, who may make their views known, within 30 days from the date of the publication of these preliminary findings.
- (iii) Any other interested party may also make known its views within 30 days from the date of publication of these findings.
- (iv) The Authority would conduct oral hearing in terms of Rule 6(6) to give an opportunity to all interested parties to present their views relevant to the investigation. Issues and concerns raised during oral hearing will be examined in the final findings.
- (v) The date of the oral hearing would be announced on the DGTR website (dgtr.gov.in).
- (vi) The Authority would conduct further verification to the extent deemed necessary.
- (vii) The Authority would disclose the essential facts as per the Rules before issuing the final findings.

BHUPINDER S. BHALLA, Addl. Secy. & Designated Authority